



Parineeti Chopra Hints At Why...

SHARE	
सेंसेक्स	: 81,361.87
निफ्टी	: 24,793.25
SARAFARANG	
सोना	: 9,445
चांदी	: 122.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

पीएम मोदी का तीन देशों का दौरा खत्म, लौटे भारत

NEW DELHI : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच दिनों का विदेश दौरा पूरा करके गुरुवार को भारत लौट आए। प्रधानमंत्री सबसे पहले 15-16 जून को साइप्रस में रहे। फिर 17 जून को कनाडा पहुंचे, 18 जून को जी-7 समिट में हिस्सा लिया। फिर क्रोएशिया गए। बुधवार को क्रोएशिया की राजधानी जगरेब में पीएम मोदी के स्वागत में संस्कृत में मंत्र पढ़े गए और भारतीय नृत्य पेश किया गया। इसके बाद मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेकोविच से द्विपक्षीय बातचीत की। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। यहां 17 हजार से ज्यादा भारतीय रहते हैं। भारत और क्रोएशिया दोनों लोकतंत्र जैसे मूल्यों से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया की पहली यात्रा पर गर्मजोशी से स्वागत के लिए वहां की सरकार और प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच का धन्यवाद किया।

पीएम मोदी ने राहुल गांधी को दी जन्मदिन की बधाई

NEW DELHI : गुरुवार (19 जून) को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 55 साल के हो गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित देश की कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं भेजकर उनके दीर्घायु होने और उमर स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्स' के माध्यम से राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें लंबा एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करें। खड़गे ने अपने पोस्ट में लिखा- राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो चीज आपको अलग करती है वह संविधान के मूल्यों के प्रति आपका ऑपरेंटिंग सर्प्रण और उन लाखों लोगों के लिए सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय के प्रति आपके गहरी करुणा जिनकी आवादी अक्षर अनसुनी कर दी जाती है।

कोरोना से अब तक 116 की मौत, 6 हजार एक्टिव केस

NEW DELHI : देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या घटकर 5976 हो गई है। बीते 24 घंटे में 507 मरीज रिकवर हुए हैं। वही 40 नए केस भी सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, जनवरी 2025 से लेकर अब तक नए वैरिएंट से 116 मौत हुई हैं। बुधवार को 3 लोगों ने जान गंवाई है। दिल्ली में 2 और केरल में एक मौत हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 1309 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा मौतें भी केरल में 37 हुई हैं। गुजरात में 1046 और पश्चिम बंगाल में 747 मामले हैं। नया वैरिएंट देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में चार नए वैरिएंट मिले हैं।

अस्त-व्यस्त हो गया जनजीवन, टूट गए पुल, पानी में फंसे कई वाहन, उफान पर नदियां झारखंड में गर्मी से राहत देकर आफत बन गई बारिश, चार की गई जान, 13 जरूमी

PHOTON NEWS RANCHI :

17 जून को झारखंड में मानसून के प्रवेश के बाद से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। गर्मी से राहत देने के बाद बारिश आफत बन गई है। गुरुवार को राज्य के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस आपदा में अब तक चार लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें तीन बच्चे शामिल हैं। वहीं 13 लोग जरूमी बताए जा रहे हैं। कई जगहों पर पुल टूट गए हैं, वाहन पानी में फंसे हुए हैं और कई लोग सुरक्षित स्थानों पर फंसे गए। मौसम विभाग की ओर से 24 जून तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। चजपात होने की भी आशंका जताई गई है। पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो दक्षिणी से उत्तरी हिस्से में होते हुए झारखंड को पार कर रहा है। इसके प्रभाव से राज्य के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश हो रही है। रांची के तमाड़ में घर गिरने से छह साल की एक बच्ची की मौत हो गई। खुंट्री के मुरहू में एक निमाणार्थीन कुएं में दो नाबालिग बच्चे दब गए। लगातार हो रही बारिश से झारखंड का हाल-

जोन्हा फॉल में बह गया एक लड़का, कहीं सड़क धंसी और कहीं घर में घुसा पानी बोकारो में खोला गया तेनुघाट डैम का फाटक, मौसम विभाग का पूर्वानुमान- 24 जून तक वर्षापात

अगले 24 घंटे में 200 मिमी वर्षा की चेतावनी

आईएमडी ने बुलेटिन में कहा है कि पिछले 6 घंटे के दौरान जिन इलाकों में 65 मिलीमीटर बारिश हुई है और पिछले 24 घंटे के दौरान जिन क्षेत्रों में 145 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, वैसे इलाकों में चिंता ज्यादा है। पश्चिमी राजस्थान, असम और मेघालय के जलाशय 90 से 99 प्रतिशत तक संचुरेशन प्वाइंट पर आ गये हैं। आईएमडी के मुताबिक, डायनामिक ग्लोबल एंड मॉडेलिंग मॉडल का पूर्वानुमान बताता है कि अगले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। चाईबासा के चक्रधरपुर लगातार बारिश के कारण एक मिट्टी का घर ढह गया, जिसमें दबने से एक महिला की मौत हो गई और तीन बच्चे घायल हो गए।



आज भी बंद रहेंगे सभी स्कूल

मौसम विज्ञान विभाग द्वारा रांची जिले को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 20 जून को भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी को देखते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री

ने जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश केजी से लेकर क्लास 12वीं क्लास के

सभी स्कूलों पर लागू होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा और सर्भाविता आपदा की स्थिति से बचाव के दृष्टिकोण से लिया गया है।

खुंट्री के अड़की में सबसे अधिक दर्ज की गई वर्षा

पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश खुंट्री जिले के अड़की में 155.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रांची में 47.2 मिमी बारिश दर्ज की गई।

इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

झारखंड के बोकारो, हजारीबाग, खुंट्री, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में भारी बारिश होगी। इसकी वजह से कहीं मध्यम तो कहीं भारी बाढ़ आने की आशंका है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय निचले इलाके हैं। इसलिए प्रशासन को समय रहते कदम उठाना चाहिए।

मौसम केंद्रों को किया गया सतर्क

आईएमडी ने कोलकाता के क्षेत्रीय मौसम केंद्र, मुंबई के क्षेत्रीय मौसम केंद्र, मौसम केंद्र भुवनेश्वर, मौसम केंद्र रांची, मौसम केंद्र अहमदाबाद और मौसम विभाग के जुड़े सभी कार्यालयों को नेशनल पलेथ पलड ग्राइडेंस बुलेटिन भेजी गयी है। इसमें ओडिशा और उससे सटे इलाकों के अलावा पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, गुजरात क्षेत्र, कोकण और गोवा मौसम केंद्रों को अलर्ट किया गया है।

अधिक बारिश में वाहन चलाने से बचें

भारी बारिश में दृश्यता कम हो जाती है, ऐसे में वाहन चलाने से बचें। यदि संभव हो तो गाड़ी किनारे रोककर बारिश थमने का इंतजार करें। कभी भी बहते पानी में गाड़ी लेकर न उतरें, सिर्फ कुछ इंच पानी भी वाहन को बहा सकता है। बाढ़ के पानी में तैरना या किसी भी तरह की गतिविधि करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह दूषित होता है।

में स्वर्णरेखा और खरकाई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।
फेज 02, 03 व 04 भी देखें।

छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को एसीबी ने किया अरेस्ट

PHOTON NEWS RANCHI :

गुरुवार को झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को अरेस्ट कर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सिद्धार्थ सिंघानिया को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे के कार्यकाल में मई 2022 में लागू उत्पादन नीति में सिद्धार्थ सिंघानिया की सक्रियता थी। छत्तीसगढ़ मॉडल पर आधारित इस नीति में सिद्धार्थ सिंघानिया महत्वपूर्ण भूमिका में था। उस समय उसने ही झारखंड को खुदरा शराब दुकानों में मैनपावर आपूर्ति का ठेका लिया था। झारखंड में शराब घोटाला केस उजागर होने के बाद से ही एसीबी की टीम सिद्धार्थ सिंघानिया से पूछताछ करने के लिए समन

शराब घोटाला



मई 2022 में झारखंड में लागू शराब उत्पादन नीति में सिंघानिया की थी सक्रियता
समन जारी होने के बाद भी जांच एजेंसी के सामने नहीं हो रहा था उपस्थित

जारी कर रही थी। वह जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हो रहा था। इसके बाद एसीबी ने कोर्ट से सिंघानिया का गिरफ्तारी वारंट लिया और फिर छत्तीसगढ़ जाकर उसे गिरफ्तार किया।

प्रसंगवश

DR. BRAJESH MISHRA @ RANCHI : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड की ओर से की जा रही शराब घोटाले की जांच के बीच झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोटाले के आरोप से खराब हुई उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की छवि को साफ करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो स्वच्छ छवि वाले अधिकारियों का चयन किया है। राज्य में अब तक आई तमाम सरकारों के समय इन दोनों अधिकारियों की कार्य प्रणाली निर्विवाद रही है। एक तरफ जहां सरकार की ओर से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल को वाणिज्य कर विभाग के सचिव के साथ ही उत्पाद विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वहीं सरायकेला-खरसावां के पूर्व उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला को उत्पाद आयुक्त

राज्य में अब तक आई सभी सरकारों के समय निर्विवाद रही है इन दोनों अधिकारियों की कार्य प्रणाली

जानें इन दोनों अधिकारियों और इनकी कार्यप्रणाली के बारे में

डॉ. अमिताभ कौशल

डॉ. अमिताभ कौशल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले यूपीएससी के 2001 बैच के झारखंड केडर के अधिकारी हैं। उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है। झारखंड के अलग-अलग जिलों में उपायुक्त के रूप में सेवा दे चुके हैं। अमिताभ कौशल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव रहे हैं। इससे पहले इन्हें झारखंड सरकार की ओर से योजना एवं वित्त विभाग के सचिव के रूप में बड़ा पहाड़ विकास परियोजना के लिए गठित तीन सदस्यीय टीम का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके जरिए इलाके में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस करते हुए लोग की जाने वाली योजनाएं तैयार कराई गईं।



बनाया गया है। उन्हें झारखंड राज्य बिजनेस जेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व

रवि शंकर शुक्ला

रवि शंकर शुक्ला 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह राज्य के पांच जिलों में उपायुक्त के तौर पर सेवा दे चुके हैं। हाल ही में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया था। इससे पहले उन्हें दुमका जिले में लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन के लिए राष्ट्रपति से भूमि पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष 2024 में इन्हें राज्यपाल ने नेशनल वॉटर डे पर बेहतर सेवा के लिए सम्मानित किया था। हजारीबाग के उपायुक्त रहते स्वच्छता के लिए किए गए कार्य के लिए शुक्ला को राष्ट्रीय



स्तर पर सम्मान प्राप्त हो चुका है। रवि शंकर शुक्ला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। पिता न्यायिक सेवा में रहे हैं। रवि शंकर शुक्ला शास्त्र ऐसे पहले आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री खुशवंत दास से लेकर हेमंत सोरेन तक ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बतौर उपायुक्त अपने गृह जिले की कमान सौंपी। इसके अलावा राज्य में पैदा हुए वैधानिक संकेत के बीच मुख्यमंत्री बने चम्पाई सोरेन के कार्यकाल के दौरान यह उनके गृह जिले सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त रहे। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग में बतौर निदेशक सेवा दे चुके हैं।

पूरा भरोसा है। यही कारण है कि कठिन हालात में इन दोनों अधिकारियों को कमान सौंपी गई है।

सिकल सेल उन्मूलन झारखंड का संकल्प मजबूत, पीड़ितों से संवाद कर सीएम हेमंत बोले-

संक्रमितों को बेहतर इलाज देने की कोशिश कर रही सरकार

PHOTON NEWS RANCHI :

विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के अवसर पर यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिकल सेल से पीड़ित युवक-युवतियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार इस रोग के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और इसे समाप्त करने के लिए एक समग्र रणनीति के तहत कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल से संक्रमितों को बेहतर इलाज और अच्छा जीवन देना हमारा प्रयास है। यह बीमारी सिर्फ मरीज को ही नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित करती है। ऐसे में यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ मिलकर लड़ें।

आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन देना सरकार की प्रतिबद्धता हेल्थ प्रोफाइल का डेटा नियमित रूप से समय-समय पर किया जाना चाहिए अपडेट

- सभी के सामूहिक प्रयासों से ही इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना संभव
- और व्यापक स्तर पर जन जागरूकता फैलाने की है जरूरत
- इस रोग की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग जरूरी
- हर स्तर पर एक समग्र रणनीति के तहत राज्य सरकार कर रही काम



हेल्थ काउंसलर की भूमिका अहम

मुख्यमंत्री ने हेल्थ काउंसलर की भूमिका को अहम बताते हुए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि काउंसलर अनुवांशिक बीमारियों की पहचान और लोगों की मानसिक तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने सिकल सेल पीड़ित युवतियां आतिथ्या कौशल, स्नेहा तिरकी, सायना परवीन, विमला कुमारी और अब्दुल हकीम अंसारी से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। एक युवती ने बताया कि बीमारी के कारण वह नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा पाती, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित होती है।

स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही इलाज संभव हो सके। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि सिकल सेल से पीड़ित व्यक्तियों को जांच, दवाइयां और रक्त की नियमित और आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

अहमदाबाद विमान हादसा

डेटा रिकवरी के लिए ब्लैक बॉक्स भेजा जाएगा अमेरिका

AHMEDABAD : एयर इंडिया हादसा में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स के विस्तृत विश्लेषण के लिए उसे अमेरिका भेजे जाने की तैयारी है। हादसे में आग लगने से ब्लैक बॉक्स को व्यापक नुकसान पहुंचने के कारण भारत में डेटा हासिल करना संभव नहीं हो पाया है। एयर इंडिया बोइंग 787 दुर्घटना में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (डीएफडीआर) की जांच वाशिंगटन स्थित नेशनल सेफ्टी ट्रान्सपोर्ट बोर्ड (एनटीएसबी) में की जाएगी। एनटीएसबी की टीम भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा और निगरानी में उसे अपनी प्रयोगशाला में ले जाएगी। यूनाइटेड किंगडम (यूके) की वायु दुर्घटना जांच शाखा के प्रतिनिधि विशेषण में भाग लेंगे, क्योंकि हादसों में 53 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। दुर्घटना की जांच के दौरान ब्लैक बॉक्स महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

बिहार में सिपाही बहाली घोटाला मामले में कार्यवाई

रांची और पटना सहित 11 ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड

PHOTON NEWS TEAM :

गुरुवार को बिहार में सिपाही बहाली घोटाला मामले में पटना की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) टीम ने बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुल 11 ठिकानों पर छापा मारा है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज इस मामले में ईडी की यह बड़ी कार्रवाई है। रांची के बरियारतू इलाके में ईडी की टीम ने जूनियर इंजीनियर रहे सिकंदर यादवेंदु के ठिकाने पर दबिश दी। पटना में डॉ. शिव के आवास पर रेड मारी गई। ईडी की टीम नालंदा (बिहार), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में

- मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई अहम दस्तावेज व डिजिटल डिवाइस जब्त
- हो सकते हैं पेपर लीक मामले से जुड़े कई और बड़े खुलासे

भी छापेमारी की। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से पेपर लीक मामले से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार, बिहार में पदस्थापित जेई रहे सिकंदर यादवेंदु को सिपाही नियुक्ति पेपर लीक मामले में पहले ही गिरफ्तार किया गया था, फिलहाल वह जमानत पर बाहर है।

VIVEK SHARMA @ RANCHI :

राज्य के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रिम्स में सेंट्रल लैबोरेट्री अब मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की जांच सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इस अत्याधुनिक लैब का निर्माण लगभग 75 लाख रुपये की लागत से किया गया है। जल्द ही ये लैब रिम्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इससे रिम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को ब्लड सैमपल देने के लिए अलग अलग विभागों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। बता दें कि रिम्स में हर दिन ओपोडी और इनडोर में इलाज के लिए 2500 मरीज पहुंचते हैं। अब तक मरीजों की विभिन्न



हर दिन ओपीडी और इनडोर में इलाज को आते हैं 2500 मरीज

75 लाख की लागत से कराया गया है सेंट्रल लैब का निर्माण


बहुत जल्द जरूरी मरीजों को इस्टॉलेशन का पूरा हो जाएगा काम

रोगियों के लिए 24 घंटे टेस्ट और रिपोर्ट की उपलब्ध रहेगी सुविधा



पुराने काउंटर के पास मरीजों की भीड़

जांचों के लिए रिम्स परिसर के अलग-अलग विभागों और फ्लोर पर जाना पड़ता है। इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। वहीं सेंट्रल और फिर रिपोर्ट लेने में पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन, अब इस सेंट्रल लैब से जांच प्रक्रिया न केवल आसान होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। मरीजों के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह सेंट्रल लैब आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित की जा रही है। चूंकि ये सेंटर ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है।



हर दिन ओपीडी और इनडोर में इलाज को आते हैं 2500 मरीज

75 लाख की लागत से कराया गया है सेंट्रल लैब का निर्माण

बहुत जल्द जरूरी मशीनों के इंस्टॉलेशन का पूरा हो जाएगा काम

योगियों के लिए 24 घंटे टेस्ट और रिपोर्ट की उपलब्ध रहेगी सुविधा

जान्चों के लिए रिस्स परिसर के अलग-अलग विभागों और फ्लोर

पुराने काउंटर के पास मरीजों की भीड़

र जाना पड़ता है। इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। वहीं

सैंपल और फिर रिपोर्ट लेने में पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन, अब

इस सेंट्रल लैब से जांच प्रक्रिया न केवल आसान होगी, बल्कि समय

एक ही जगह सैल कलेक्शन का इंतजाम

सेंट्रल लेब में पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार की टेस्ट होंगी। इसमें ब्लड, यूरिन, स्टूल और अन्य टेस्ट के साथ-साथ रासायनिक स्तर, बैक्टीरिया-वायरल संक्रमण की पहचान के अलावा कई महत्वपूर्ण सेवाएं भी एक ही स्थान पर मिलेंगी। भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब लेब में जरूरी मशीनों का इंस्टॉलेशन किया जाना है। रिस्क को ऑटो एनालाइजर, यूरिन ऑटो एनालाइजर, कोएग्युलेशन एनालाइजर और हीमेटोलॉजी एनालाइजर जैसी आधुनिक जांच मशीनों का इंतजाम है। मशीनों के इंस्टॉल होने के बाद ही लेब पूर्ण रूप से फंक्शनल हो जाएगा।

ग्राउंड फ्लोर पर बने काउंटरों से मिलेगी रिपोर्ट

सेंट्रल लेब चालू होने के बाद 24 घंटे ब्लड टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मरीज कभी भी जांच करावा सकेगा और ग्राउंड फ्लोर पर बने काउंटरों से रिपोर्ट प्राप्त कर सकेगा। साथ ही, रिपोर्टर्स को डिजिटल रूप में मोबाइल पर भी उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे मरीजों को बार-बार अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे भी मरीजों को बड़ी राहत मिल जाएगी। सबसे बड़ी राहत की बात ये होगी कि मरीजों को रिपोर्ट के लिए अगले दिन का इंतजाम नहीं करना होगा। ऐसे में उनका इलाज भी तत्काल शुरू हो जाएगा।

तेज होगी इलाज की प्रक्रिया

रिस्क के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि नई सेंट्रल लेब मरीजों के लिए राहत लेकर आएगा। अब उन्हें रिपोर्ट के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। टैंड टेक्नीशियन और आधुनिक मशीनों की सहायता से सटीक और समय पर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया भी तेज होगी।

नामकुम में पुलिया के ऊपर से बह रहा पानी, सुरक्षित स्थानों पर लोगों से शरण लेने की अपील

बांधगाड़ी में डूब गए कई अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर

निवारणापुर में पुल से बहती हरमू नदी

जल निकासी का इंतजाम नहीं

मानसून की पहली बारिश में रांची नगर निगम की व्यवस्था की पोल खुल गई। जल निकासी के इंतजाम पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। नालियाँ ओवर फ्लो बह रही हैं। जिससे पूरा कवरा लोगों के घरों में पहुंच गया है। निचले इलाकों में लोग परेशानी हैं। गंदगी के कारण उन्हें बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से राहत देने की गुहार लगाई है। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है।

नामकुम में फंसे लोगों को किया रेस्क्यू

बच्चों को शिफ्ट किया गया ऊपर

निवारणापुर स्थित शिफ्टिंग मूक बधिर स्कूल में हरमू का पानी घुस गया है। वहीं नालों का पानी स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर भर गया। ऐसे में तत्काल बच्चों को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। पानी भर जाने से बच्चों को परेशानी हो रही है। चूंकि टॉयलेट बाथरूम भी जलमग्न हो चुका है।

हरमू और पिरका मोड़ की स्थिति विकट

रांची में कई इलाकों में जलजमाव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में बांधगाड़ी, हरमू और पिरका मोड़ शामिल हैं। बांधगाड़ी क्षेत्र में स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहां के कई अपार्टमेंट और घरों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बारिश का पानी घरों के अंदर घुस गया, जिससे कुछ लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कुछ परिवार अपना सामान छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल रहे हैं।

ढह गई बाउंड्री की दीवार

पिरका मोड़ क्षेत्र में भारी बारिश के चलते एक बाउंड्री वॉल ढह गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। वहीं हरमू क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भरने से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है और लोग घरों में ही दुबक कर बैठे हैं। कुछ इलाकों में तो नालियाँ ओवर फ्लो हो रही हैं।

के पास नहीं पहुँच पाते। पंचायत
स्तर पर संगठन मजबूत नहीं हो
के कारण लोकसभा विधानसभा
चुनाव में प्रत्येक वृथ पर 10 से
50 के बीच कांग्रेस समर्थक वोट
मतदाता मतदाता केंद्र तक नहीं
पहुँच पाए। इसके कारण हम का
सीटों पर बहुत कम मों के अंत
से चुनाव हारें। उन्होंने उपस्थित
पर्वविक्षकों से कहा कि प्रथम चरण
में छूटे हुए प्रखंड अध्यक्षों के
झारखंड एप में रजिस्टर्ड करना है
और मंडल अध्यक्षों को भी
रजिस्टर्ड कर प्रखंड अध्यक्ष
पर्वविक्षक और मंडल अध्यक्षों का
प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने
है। 214 प्रखंड अध्यक्ष एप में
रजिस्टर हो चुके हैं।

RANCHI : प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान खान ने कहा कि झारखण्ड अब पीछे नहीं, सिकल सेल उन्मुख न में देश का मॉडल राज्य बन गया है। उन्होंने कहा, हमने 25 लाख 94 हजार लोगों की जांच की है। इनमें से मात्र 2099 लोग सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त पाए गए हैं, यानी एक प्रतिशत से भी कम। ये हमारे संगठित प्रयास और जमीनी काम का नतीजा है। डॉ. अरुण गुरुवार को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर रांची सदर अस्पताल में आयोजित राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, नर्स, एनएएम, सहिया दीदियां आप सब हमारे सच्चे बहनों हैं। आप मेहनत करें, सेसरी बढ़ाएं का काम हम करेंगे। सभी सहिया बहनों को जल्द ही टेबल्ट की दिया जाएगा ताकि तकनीकी के साथ आप और तेजी से काम कर सकें।

PHOTON NEWS RANCHI :
रांची में हो रही भारी बरसात का फायदा चोर भी उठाने लगे हैं। ताजा मामला रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र का है। यहां एक जेवर दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है और लाखों के गहने ले उड़े। मामला बुधवार की देर तक इधर है। पिठौरिया के रणधीर कॉम्प्लेक्स में स्थित सचिट ज्वेलर्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए उससे सटे जुटा दुकान की दीवार को तोड़ दिया। चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने जेवर दुकान के शटर को नहीं काटा, क्योंकि

पिस्का मोड़ के आगे व इटकी रोड पर कुछ दूर तक बनाया गया है पलाईओवर एनएच-75 से जुड़े रातू रोड पर 3.57 किमी लंबा पलाईओवर बन जाने से आसान होगा आवागमन

» तीन जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करंगे उद्घाटन, तैयारी मुकम्मल

» कचहरी की ओर जाकिर हुसैन पार्क के पास पूरा हो चुका है रैप का निर्माण कार्य

» राजभवन के समीप हर स्तर पर किए गए हैं सुरक्षा के बेहतर उपाय

» नवंबर 2022 में शुरू किया गया था निर्माण कार्य, निर्धारित समय से लगे पांच माह अधिक



कॉरिडोर का रैप 600 मीटर लंबा

पलाईओवर के दोनों ओर पिस्का मोड़ व कचहरी की ओर जाकिर हुसैन पार्क के पास रैप बनकर तैयार है। कचहरी पास के मंदिर-यात्रा को पहले ही हटा दिया गया है। अब इस फ्लाईओवर में वाहनों के परिचालन में कोई असर नहीं है। इसके बन जाने के बाद सालों पहले जिस तहत रातू रोड पांच-सात मिनट में पार हो जाता था, अब फिर से हो सकेगा। पलाईओवर के नीचे सदर्रीकरण का काम चल रहा है, रंग-रोगन के अलावा घास लगाए जा रही है। लाइटिंग भी आकर्षक है। राजभवन के समीप सुरक्षा के भी बेहतर उपाय किए गए हैं। रातू रोड में कचहरी से पिस्का मोड़ तक (करीब 2.5 किमी)

का यात्रा पूरा करने में आधा घंटा से 45 मिनट तक लगता था। लेकिन अब एनएच-75 से जुड़े रातू रोड पर 3.57 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर के बन जाने से यह सफर आसान हो गया है। इस कॉरिडोर को बनाने में दो साल से कुछ अधिक समय लगा है। कॉरिडोर का रैप 600 मीटर लंबा है। इसका निर्माण कार्य नवंबर 2022 में शुरू हुआ था और जनवरी 2025 (22 महीने) में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन, जमीन अधिग्रहण और कुछ अन्य तकनीकी कारणों से एलिवेटेड कॉरिडोर को पूरा होने में निर्धारित समय से लगभग पांच माह का ज्यादा समय लगा।



- तीन दिनों से लगातार बारिश से नदियां व जलाशय हुए लबालब
- खरकई व स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर

- निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर
- बागबेड़ा में नया बस्ती के निचले इलाके में कई घरों में घुसा पानी

जमशेदपुर में खतरे के निशान से ऊपर बहती स्वर्णरेखा नदी

लगातार बारिश से कोल्हान हुआ पानी-पानी

PHOTON NEWS TEAM : लगातार बारिश की वजह से पूरा कोल्हान पानी-पानी हो चुका है। गलियों से लेकर सड़कों तक को बारिश ने सराबोर कर दिया है। कोल्हान की दो प्रमुख

नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। निचले इलाकों में लोगों को सचेत कर दिया गया है। जमशेदपुर के बागबेड़ा

स्थित नया बस्ती के निचले इलाके में करीब 40-50 घरों में बरसात का बानी घुसने की सूचना है। दूसरी ओर मौसम के मिजाज को देखते हुए स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा कर दी

गई है। मानगो स्थित पारडीह में तो काली मंदिर के समीप एनएच-33 तालाब की शफल में तब्दील हो चुका है, जहां नाव चल रही है। पढ़े-यह रिपोर्ट।



तालाब की शफल में तब्दील एनएच-33 पर चल रही नाव व डूबी कार

PHOTON NEWS JSR :

नदियों का जलस्तर

पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर अब नदियों के जलस्तर पर साफ दिखने लगा है। गुरुवार को स्वर्णरेखा और खरकई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यही नहीं, इनका जल स्तर लगातार ऊपर उठ रहा है। इससे मानगो, शास्त्री नगर, बागबेड़ा आदि इलाकों में 150 से अधिक मकान डूब गए हैं। स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से 1.20 मीटर ऊपर और खरकई नदी खतरे के निशान से लगभग 3.0 मीटर ऊपर बहने लगी है। इन दोनों नदियों के आसपास का इलाका जलमग्न हो गया है। बागबेड़ा, मानगो और शास्त्री नगर में निचले और तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे लोगों और डूब क्षेत्र में रहने वालों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर ऊंचे एवं सुरक्षित स्थानों पर शरण लें।

कई इलाके जलमग्न, हाथ पर हाथ धरे बैठा नगर निगम

जमशेदपुर, बागबेड़ा और मानगो आदि कई इलाकों में पानी भर गया है। मानगों में दर्जनों मकान जलमग्न हो गए हैं। कई घरों में गंदा पानी घुस गया है। कई अपार्टमेंट में जल भराव से लोग परेशान हैं। लोग अपने अपार्टमेंट में नजर बंद होकर रह गए हैं। नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इलाके के लोगों ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता से शिकायत की। इसके बाद पूर्व मंत्री ने नगर निगम

हालांकि दोनों नदियों का जलस्तर अभी खतरे के निशान से थोड़ा नीचे है, लेकिन लगातार बारिश से पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे किसी भी प्रकार की गतिविधियों से बचने की सख्त हिदायत दी है। प्रशासन ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

के अधिकारियों को समस्या हल करने का निर्देश दिया। नगर निगम के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने नाला सफाई करने वाले ठेकेदार को मौके पर भेजा। लेकिन मानगो नगर निगम के कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर लाचारी जताई। कहा कि उनके पास कोई लेबर नहीं है।

चक्रधरपुर में मिट्टी का घर ढहने से दर्दनाक हादसा, मां की मौत, तीन बच्चे हुए घायल

CHAKRADHARPUR : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के कुलीतोडांग पंचायत में गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना लगातार हो रही बारिश के कारण एक मिट्टी के कच्चे घर के ढह जाने से हुई। गांव निवासी रमिया दोगे की पत्नी गुरुवारी दोगे अपने दो बच्चों और एक रिश्तेदार बच्ची के साथ घर में थी, तभी अचानक मकान भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबने से गुरुवारी दोगे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीनों बच्चे घायल हो गए। घायलों में 3 साल का गुलशन दोगे, 5 महीने का सुनिल दोगे और 8 साल की इन्दा पूर्ति शामिल है, जो चांदबासा के कुसमुंडा गांव से मेहमान के रूप में आई थीं। घटना के बाद मुखिया माझीराम जोको और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को चक्रधरपुर



अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉ. अशुमन शर्मा ने गुरुवारी दोगे को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल तीनों बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है और वे खतरे से बाहर हैं।

प्रशासन मौके पर, राहत व सहायता का भरोसा : घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर के प्रखंड विकास



घाटशिला में बारिश ने बंद किए घरों के दरवाजे, निकलना हुआ मुश्किल

GHATSILA : प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार की शाम से लगातार हो रही बारिश से पूरा जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुवार को फुलडुंगरी चौक स्थित दर्जन भर दुकानों में 2 फीट से अधिक पानी जमा हो जाने से काफी नुकसान हुआ। शंकर बीज भंडार का सैकड़ों बोरा धान का बीज पानी में डूब गया है। दुकानदारों का आरोप है कि हाल ही में फुलडुंगरी चौक से गोपालपुर रेलवे ओवरब्रिज तक बनी सड़क की ऊंचाई बढ़ जाने के कारण दुकान के अंदर पानी घुस रहा है। इतना ही नहीं फुलडुंगरी चौक के पास बने कलवट को फोरलेन बनाने के समय एनएचआई ने बंद कर दिया था। इस वजह से बरसात का पानी निकलना बंद हो गया है।

वन विभाग कार्यालय डूबा : घाटशिला प्रखंड के पावड़ा पंचायत एवं काशिदा पंचायत से सटा गांव प्रेम नगर के चारों ओर सड़क से लेकर खेत तक पानी भर जाने से गांव के लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि पानी कम होने पर घर से निकाल पाएं। वन विभाग के कार्यालय में पानी घुस गया है।

बिजली आपूर्ति टप : तेज बारिश के कारण धरमबहाल फुलडुंगरी एवं पावड़ा गांव में बुधवार की शाम से ही विद्युत आपूर्ति टप हो गई है। इस क्षेत्र के लिए कॉलेज रोड में लग 200 केवी का ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आज कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में कक्षाएं स्थगित

JAMSHEDPUR : मौसम विभाग (IMD) से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 24 घंटों में जिले में लगातार भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। साथ ही अप्रत्याशित वृष्टि के कारण जल जमाव एवं नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे जन-जीवन एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। डीसी कर्ण सत्यार्थी द्वारा उक्त परिस्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत जिले के कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी कोटि के सरकारी, निजी, अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में शुक्रवार को आज अवकाश घोषित किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के डीसी चंदन कुमार ने भी अपने जिले कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी कोटि के सरकारी, निजी, अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में शुक्रवार को आज अवकाश घोषित किया गया है। यह आशंका एहतियातन तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जनिहैत में जारी किया गया है, जिसका पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।



डीएवी बिष्टुपुर में छुट्टी गेट पर गिरा पेड़

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में बुधवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश को देखते हुए बिष्टुपुर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल ने एहतियात बरतते हुए नर्सरी से लेकर कक्षा बारहवीं तक के सभी छात्रों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। स्कूल प्रशासन ने शिक्षकों को भी अवकाश दिया है, हालांकि कार्यालय खुला रहेगा। इस बीच, डीएवी पब्लिक स्कूल के गेट नंबर 4 के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया है। पेड़ गिरने से उस मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। इसके साथ ही, पेड़ गिरने के कारण स्कूल की बाउंड्री वॉल को भी नुकसान पहुंचा है।

सरायकेला में मूसलाधार बारिश से नदियां उफनाईं, जनजीवन हुआ प्रभावित

SERAIKELA : पिछले तीन दिनों से झारखंड में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने सरायकेला-खरसावां जिले में भी भारी तबाही मचाई है। बारिश के कारण शहरी इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। जर्जर ड्रेनेज सिस्टम के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है।

रेलवे ट्रेन के नीचे जलजमाव से संपर्क टूटा : कोलेबिरा के पास रेलवे पुल के नीचे भारी जलजमाव के कारण लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासन अलर्ट, तटीय इलाकों का दौरा : संभावित बाढ़ के खतरे



नदी का जायजा लेते प्रशासनिक अधिकारी

● फोटोन न्यूज़

को देखते हुए प्रभारी एसडीओ निवेदिता नियती ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आदित्यपुर और गम्हरिया के तटीय इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ अंचल और नगर निगम प्रशासन की टीम भी मौजूद थी। प्रभारी एसडीओ ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। उन्होंने नगर निगम को एहतियाती कदम उठाते हुए शेल्टर होम और सामुदायिक भवनों में व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, मछुआरों को भी नदी में नहीं जाने की सख्त सलाह दी गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण खरकई नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और वह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले से होकर बहने वाली दो प्रमुख नदियां, स्वर्णरेखा और खरकई, दोनों ही खतरे के स्तर को पार कर चुकी हैं, जिससे सरायकेला-खरसावां जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

बहरीन से लौटते ही एयरपोर्ट पर कुख्यात निसार गिरफ्तार

JAMSHEDPUR : कई आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात निसार हसन उर्फ निशु को दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। वह



सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद निशु का एक वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उसने दावा किया कि दिल्ली

बहरीन से दिल्ली पहुंचा ही था कि एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में जमशेदपुर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एक विशेष टीम राजधानी के लिए रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि निशु जमशेदपुर में दर्ज गंभीर मामलों में नामजद है। साल 2022 में मैंगेस्टर गणेश सिंह पर हुए बम हमले में उसकी संलिप्तता भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा उस पर हत्या, रंगदारी, आपराधिक षड्यंत्र पुलिस ने उसे पकड़ा है और अब उसे डर है कि कहीं जमशेदपुर पुलिस उसका एनकाउंटर न कर दे। उसने कहा, मुझे सुरक्षा चाहिए, मैं कानून के आगे पेश होने को तैयार हूँ जमशेदपुर पुलिस सूत्रों के अनुसार, निशु की गिरफ्तारी लंबे समय से वांछित थी। उसके खिलाफ गिरोहबंदी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की तैयारी है। जमशेदपुर पुलिस की टीम शुक्रवार सुबह तक उसे ट्रॉजिट रिमांड पर लेकर झारखंड ला सकती है।

जिले के मात्र तीन कॉलेजों में हो रहा इंटरमीडिएट में नामांकन, कहां जाएं विद्यार्थी

डिग्री कॉलेजों में इंटर बंद करने से आंदोलन के मूड में छात्र

PHOTON NEWS CHAIBASA :

राज्य में इंटरमीडिएट की पढ़ाई का मामला गरमा रहा है। इस मुद्द पर छात्र संगठन आंदोलन की तैयारी में हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले की बात करें तो इस जिले में मात्र तीन प्लस टू कॉलेज हैं है जिसमें वहां के पढ़े विद्यार्थियों को ही को नामांकन में प्राथमिकता मिलती है। ऐसे में टाटा कॉलेज, महिला कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज एवं ग्रामीण गांव क्षेत्र से अध्ययन करके आने वाले विद्यार्थियों को नामांकन से वंचित रहना पड़ता है। यह कहना है झामुमो छात्र मोर्चा के नेताओं का।



मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे छात्र-छात्राएं : बारीक

टाटा कॉलेज छात्र संघ के पूर्व सचिव पिपुन बारीक ने कहा कि राज्य के अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद की जाने से छात्र-छात्राओं को मानसिक प्रताड़ना से जूझना पड़ रहा है एवं छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। जल्द ही सरकार द्वारा इस समस्या को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो छात्र संघ आगामी दिनों में राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगी।

गरीब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ : हंसदा

छात्र नेता सह झामुमो जिला युवा मोर्चा सचिव मंजीत हंसदा ने कहा कि केन्द्रीय शिक्षा नीति 2020 का नियम के अनुसार राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा जारी नोटिफिकेशन खिलाफ है क्योंकि जिला में छात्रों के पर्याप्त इंटर कॉलेज नहीं बने है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद किए जाने के निर्णय का कड़ा विरोध करते हैं। मंजीत हंसदा ने कहा कि यह निर्णय ग्रामीण एवं गरीब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। मंजीत हंसदा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा पढ़ाई पुनः शुरू नहीं की गई, तो छात्र आंदोलन करने को विवश होंगे। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि शिक्षा से कोई भी वंचित न हो, इसके लिए जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए।

इंटर की पढ़ाई को पुनः कराएं : सनातन पिंगुवा

छात्र नेता सनातन पिंगुआ ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि ग्रामीण क्षेत्र के हजारों छात्र-छात्राएं इस समय शिक्षा से वंचित हो रहे हैं क्योंकि उनके निकटवर्ती सरकारी महाविद्यालय एवं इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई है। गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्र प्राइवेट संस्थानों की भारी फीस वहन नहीं कर सकते। सनातन ने कहा कि यह निर्णय न केवल छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन है। सनातन पिंगुवा ने कहा छात्र-छात्राओं और अभिभावकों में भारी आक्रोश है सरकार से मांग है कि तत्काल कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई को पुनः शुरू किया जाए।



कब और किसे नहीं खाना चाहिए कद्दू

कद्दू विटामिन ए से भरपूर होता है। यह त्वचा, हड्डी और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये फाइबर से भरपूर है जो कि कई बीमारियों से बचाता है। ये पेट का मेटाबोलिक रेट बढ़ाता है और पाचन क्रिया को तेज करता है। कद्दू में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे अल्फा-कैरोटीन, बीटा-कैरोटीन और बीटा-क्रिप्टोक्सैन्थिन। ये एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों को बेअसर कर सकते हैं और आपकी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं। लेकिन, हर स्थिति में कद्दू खाना

फायदेमंद नहीं है। क्यों जानते हैं इस बारे में।

पेट सही न हो तो कद्दू न खाएं : कद्दू खाना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (जीआई) इफेक्शन से जुड़े लक्षणों को बढ़ा सकता है। इसकी वजह से आपको फूड एलर्जी हो सकती है। इससे अलावा कद्दू खाना पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है जिससे समस्याएं और बढ़ सकती हैं।

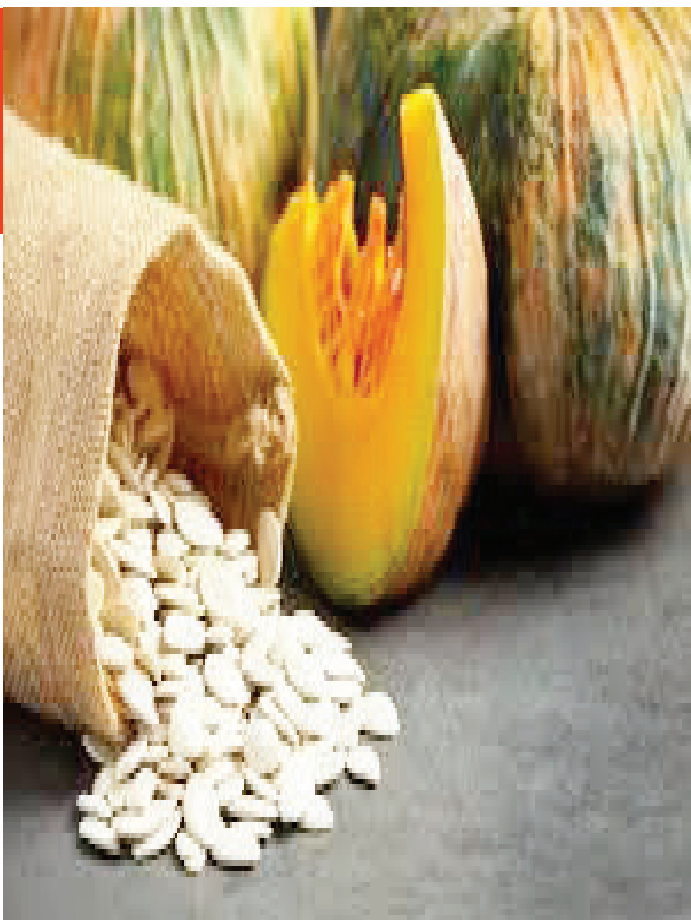
फूड प्वाइजनिंग हो सकती है : कद्दू खाना बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों को प्रसारित कर सकता है जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। ये फूड प्वाइजनिंग की वजह बन सकता है और आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। इसे खाने के बाद उल्टी, मतली और कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है और ये दस्त समेत शरीर को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

गर्भवती हैं या स्तनपान कराने वाली मां : जो लोग

गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, उन्हें इसे खाने से बचना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन करने से पहले हमेशा अपने आहार के बारे में डॉक्टर से जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसे खाना उनके लिए सुरक्षित है या नहीं।

कुछ दवाओं के कारण नुकसान : कद्दू के पोषक तत्व शरीर को पानी की मात्रा को जल्दी से खत्म करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं यानी कि डिहाइड्रेट कर सकते हैं। जो इस बात पर असर डाल सकता है कि शरीर लिथियम जैसी कुछ दवाओं को कैसे अवशोषित करता है। इसलिए दवाओं के साथ कद्दू खाने से बचें।

लो बीपी में : कद्दू के बीज में बीटा कैरोटीन और मैग्नीशियम होता है जो ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन, अगर आप हाई बीपी की दवाओं जैसी दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो अपने आहार में कद्दू को शामिल करने से पहले डॉक्टर से बात करें। तो, इन तमाम स्थितियों में कद्दू खाने से बचें।



खाना खाने के कितनी देर के बाद पानी पीना चाहिए?

कुछ लोग खाना खाने से पहले पानी पीते हैं, तो वहीं कुछ लोग खाना खाते-खाते पानी पी लेते हैं और कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना खाते-खाते या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की वजह से आपको सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? आइए जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर आपको खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए।

30 मिनट के बाद पिएं पानी

आयुर्वेद के मुताबिक आपको खाना खाने के कम से कम 20-30 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। अगर आप खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीते हैं, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर नहीं पड़ता है। यानी अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बचना चाहिए।

खाने के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होता है?

खाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपकी गट हेल्थ बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। आपकी इस आदत की वजह से आपको पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खाने के एकदम बाद पानी पीने से डाइजेशन प्रोसेस धीमा हो जाता है। यही वजह है कि आयुर्वेद में खाने के तुरंत बाद पानी पीने से मना किया जाता है।

गौर करने वाली बात

आयुर्वेद के मुताबिक खाने को अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। अगर आप बड़ी-बड़ी बाइट्स बिना चबाए निगल जाएंगे, तो आपकी गट हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है और आप पेट से जुड़ी समस्याओं का शिकार बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाए, तो आपको खाने और सोने के बीच में भी कम से कम दो से तीन घंटे का गैप रखना चाहिए।



मधुमेह के मरीज रोज सुबह खाली पेट पी लें इस सूखे पत्ते की चाय

रसोई में ऐसे कई मसाले हैं जिनका इस्तेमाल बीमारियों में दवा का काम करता है। शुगर से लेकर हाई ब्लड प्रेशर तक को कंट्रोल करने में ये मसाले या पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। मधुमेह में कई घरेलू नुस्खे असरदार साबित होते हैं। जिनका लगातार इस्तेमाल करने से शरीर में ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगता है। ऐसा ही सूखा पत्ता है तेज पत्ता, जिसका इस्तेमाल गरम मसाले में करते हैं। तेज पत्ता काफी खुशबूदार होता है। डायबिटीज के मरीज अगर सुबह खाली पेट तेज पत्ता की चाय बनाकर पीते हैं तो इससे शुगर को कम करने में फायदा मिलता है।

तेज पत्ता को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। तेज पत्ता में भरपूर एंटी-ऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व डायबिटीज में असरदार साबित होते हैं। तेज पत्ता में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम और कॉपर होता है। कुछ दिनों तक नियमित रूप से तेज पत्ता का पानी या

चाय पीने से पुरानी से पुरानी डायबिटीज को कम किया जा सकता है।

शुगर में तेजपत्ता के फायदे

आयुर्वेदिक डॉक्टरों की मानें तो शुगर को कम करने के लिए कई तरह की जड़ी बूटियां हैं जो आपके घर में भी आसानी से मिल जाती हैं। आचार्य बालकृष्ण की मानें तो डायबिटीज में तेज पत्ता काफी फायदेमंद है। कई रिसर्च में भी ये सामने आ चुका है कि डाइट और एक्सरसाइज के साथ कुछ आयुर्वेदिक उपाय करने से शुगर कम होने लगती है। ऐसा करने से इंसुलिन फंक्शन में सुधार आता है।

शुगर में तेज पत्ता की चाय?

तेज पत्ता का इस्तेमाल खाने में तो सभी करते हैं। लेकिन डायबिटीज के मरीज को इसकी चाय या पानी पीना चाहिए। तेज पत्ता की चाय बनाने के लिए 1 तेज पत्ता 1 गिलास पानी में डालकर रातभर के लिए भिगो दें। सुबह इस पानी को उबालकर

छानकर पी लें। आप चाहें तो अपनी नॉर्मल दूध वाली चाय में भी तेज पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तेज पत्ता की चाय में थोड़ी दालचीनी, इलायची और तुलसी डालकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। नॉर्मली आप सुबह खाली पेट तेज पत्ता का पानी पी सकते हैं। इससे धीरे-धीरे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने लगेगा।

इन बीमारियों में फायदा करता है तेज पत्ता

तेज पत्ता न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि कई बीमारियों में भी असरदार काम करता है। तेज पत्ता का सेवन करने से पेट की समस्या जैसे कब्ज, एसिडिटी, मरोड़ और दर्द को कम किया जा सकता है। अगर किडनी में स्टोन हो रहे हैं तो तेज पत्ता का पानी पीने से फायदा मिलेगा। जिन लोगों को नौद की समस्या रहती है। वो तेज पत्ता के तेल की कुछ बूंदें पानी में डालकर पी लें। जोड़ें पर तेज पत्ता के तेल से मसाज करना राहत पहुंचाता है।

सेहत के लिए वरदान साबित होगी लेमनग्रास टी

क्या आप जानते हैं कि सही मात्रा में और सही तरीके से लेमनग्रास चाय पीने से आप सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेमनग्रास टी में विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट समेत कई पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लेमनग्रास टी पीने की सलाह देते हैं। आइए इसके पीछे छिपे कुछ कारणों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।

गट हेल्थ के लिए फायदेमंद

लेमनग्रास टी में पाए जाने वाले तमाम तत्व आपकी गट हेल्थ को काफी हद तक सुधार सकते हैं। एसिडिटी और पेट दर्द जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप लेमनग्रास टी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा लेमनग्रास टी आपकी बॉडी के मेटाबोलिज्म को बूस्ट कर आपकी वेट लॉस जर्नी को भी काफी हद तक आसान बना सकती है।

बूस्ट करे इम्यूनिटी



विटामिन सी रिच लेमनग्रास टी को रेगुलरली कंज्यूम करने से आप अपने इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बना सकते हैं। लेमनग्रास टी न केवल कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ को सुधारने में भी कारगर साबित हो सकती है। जोड़ों के दर्द की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी लेमनग्रास टी का सेवन किया जा सकता है।

मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेमनग्रास टी न केवल आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप तनाव और चिंता को कम करना चाहते हैं, तो लेमनग्रास टी पीना शुरू कर दीजिए। कुल मिलाकर अपनी ओवरऑल हेल्थ को सुधारने के लिए लेमनग्रास टी को अपने डेली डाइट प्लान का हिस्सा बनाया जा सकता है।

फायदा ही नहीं सेहत को नुकसान भी पहुंचाता है ओट्स

जानें किन लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए?

ओट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह सुपरफूड अपने हाई फाइबर और हृदय स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। रात भर भिगोए गए ओट्स से लेकर ओट्स चीला तक, इस अनाज को खाने के कई तरीके हैं। यानी नाश्ते के लिए ओट्स एक हेल्दी विकल्प है, लेकिन कुछ लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए। चलिए जानते हैं वे लोग कौन हैं?

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए ओट्स:

एलर्जी होने पर : ओट्स से एलर्जी बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित कर सकती है। ओट्स एलर्जी के लक्षणों में पित्ती, जठरांत्र संबंधी, श्वसन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। इसलिए, ओट्स से एलर्जी वाले लोगों को ओट्स के उत्पादों का सेवन करने से बचना चाहिए।

इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित : ओट्स में घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन, ओट्स में मौजूद हाई फाइबर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले लोगों में यह समस्या हो सकती है। इससे पेट में सूजन, गैस और तकलीफ पैदा हो सकती है।

मिनिरल्स की कमी होने पर : ओट्स में फाइटिक एसिड होता है, जो एक एंटीन्यूट्रिएंट है जो कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे आवश्यक मिनिरल्स से जुड़ सकता है, जिससे शरीर में अवशोषण कम हो जाता है। हालांकि यह स्वस्थ लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन जिन लोगों में मिनिरल्स की कमी है या जो लोग मुख्य रूप से ओट्स खाते हैं, उन्हें कम मात्रा में ओट्स खाना चाहिए।

किडनी की बीमारी से पीड़ित लोग : ओट्स में फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जो किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए किडनी की बीमारी वाले लोगों को ओट्स खाने से बचना चाहिए।

डायबिटीज के मरीज : ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकते हैं, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर से सलाह लेकर ही ओट्स खाना चाहिए।



खाने के बाद करें 10 मिनट की वॉक

रोजाना वॉक करके आप सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को दूर भगा सकते हैं। लेकिन क्या आप खाना खाने के बाद वॉक करने के कुछ कमाल के हेल्थ बेंनिफिट्स के बारे में जानते हैं? दादी-नानी के जमाने से खाना खाने के बाद वॉक करने की सलाह दी जाती रही है। जो लोग रेगुलरली टहलते हैं, उनका शरीर बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा ताकतवर बन जाता है। आइए जानते हैं कि खाना खाने के बाद वॉक क्यों करनी चाहिए... आपको हर रोज खाना खाने के बाद महज 10 मिनट निकालकर टहलना चाहिए। एक हफ्ते तक इस नियम को बिना तोड़े फॉलो कीजिए और आपको खुद-ब-खुद पॉजिटिव असर देखने को मिल जाएगा। हालांकि, खाना खाने के बाद आपको ज्यादा तेज स्पीड में वॉक नहीं करनी चाहिए वरना आपके शरीर पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव असर भी पड़ सकता है।

मिलेंगे फायदे ही फायदे - खाने के बाद वॉक करने से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको इस नियम को जरूर फॉलो करना चाहिए। खाने के बाद वॉक करने से न केवल आपकी बॉडी के मेटाबोलिज्म को बूस्ट किया जा सकता है बल्कि आपकी गट हेल्थ को भी काफी हद तक सुधारा जा सकता है।

राहुल गांधी के 'मिशन बिहार' को बड़ा झटका- अब कांग्रेस क्या करेगी?



महागठबंधन के सबसे बड़े दल के तौर पर राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जबकि कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आई थीं। सीपीआई-माले 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाले मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी इस बार विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी की पार्टी को सीट बंटवारे में एडजस्ट करने की चुनौती है वहीं लेफ्ट फ्रंट के दल खासकर सीपीआई-माले सीट बढ़ाने की मांग को लेकर अड़ गया है। ऐसे में लालू यादव भी अपनी पार्टी के कोटे को घटाने पर तैयार हो

का हेरफेर किया जा सकता है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में पशुपति पारस, असदुद्दीन ओवैसी, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव को भी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन में शामिल किया गया तो फिर सभी दलों को त्याग करना पड़ेगा। ऐसे हालात में, कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 45-46 सीटें ही आ पाएंगी। यानी लालू यादव के पहले फॉर्मूलें के तहत कांग्रेस को 53-55 और दूसरे फॉर्मूलें के तहत सिर्फ 45-46 सीटें ही मिल सकती हैं। आपको याद दिला दें कि, वर्ष 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राजद मुखिया लालू यादव जेल में थे। यह आरोप लगाया जाता है कि लालू यादव के जेल में रहने का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने तेजस्वी यादव पर दबाव डालकर गठबंधन में 70 सीटें झटक लीं। लेकिन 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। लालू यादव और तेजस्वी यादव सहित विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं का यह मानना है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण ही बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए थे। लालू यादव 2020 के विधानसभा चुनाव के समय पर जेल में थे लेकिन इस बार बाहर है और सीट बंटवारे के अपने फॉर्मूलें पर अडिग है। राजद के इस फॉर्मूलें ने कांग्रेस नेताओं को दुविधा की स्थिति में डाल दिया है। अब गैर राहुल गांधी के पाले में है कि वह इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं या सीधे लालू यादव से बात करके कांग्रेस के कोटे की सीटों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करें। हालांकि बिहार में कांग्रेस के कई नेता दबी जुबान में एक तीसरे विकल्प की बात भी कर रहे हैं। तीसरा विकल्प यानी राहुल गांधी बिहार में अन्य छोटे-छोटे दलों को साथ लेकर तीसरा मोर्चा बनाए और बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ जाएं।

संपादकीय

ट्रंप की नृराकुशती

मध्य-पूर्व में अमेरिका और इराक़ को नया शिकार मिल गया है। ट्रंप और नेतनयाहू की जुगलबंदी से ईरान तबाही की ओर बढ़रू रहा है। अलग-थलग पड़ चुका ईरान कितना प्रतिरोध कर पाएगा यह तो भविष्य ही बताएगा क्योंकि जहां से मदद की उसे उम्मीद थी वह रूस तीन साल से यूक्रेन से पार नहीं पा सका है, और चीन इराक़ को संयम रखने वाली नसीहतें देकर काम चला रहा है। इस समय दुनिया की जो हालत है उसमें सबने अपने-अपने टारगेट तय किए हुए हैं, चीन को भी कालांतर में ताइवान से निपटना है। ट्रंप की चेतार्वनियों से तो लगता है कि अमेरिका युद्ध में कूद ही पड़ा है। अमेरिका पहले अपने शत्रु तैयार करता है और फिर विध्वंसक रासायनिक, परमाणु हथियार बनाने और लोकतंत्र हनन के अनर्गल आरोप लगा कर लड़ाई करता है। इराक़, अफगानिस्तान, लांबिया और सीरिया की तबाही इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। दरअसल, अमेरिका की मजबूत हथियार लांबी, जो नये-नये हथियार

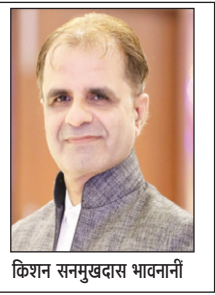


इजाद करती है, के हथियारों का कहीं परीक्षण भी तो होना चाहिए। युद्ध के बहाने हथियारों का परीक्षण हो जाता है और कई देश दहशत में भी आ जाते हैं। हथियारों की बिक्री का यह उसका आजमाया हुआ तरीका है। इराक़ल की मदद के बहाने अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा है जो ईरान उसके साथ पांच दौरे की परमाणु वार्ता कर चुका था, छठे दौर की वार्ता से ठीक पहले अमेरिका ने इराक़ल को उकसा कर हमला करवा दिया। ईरान परमाणु हथियार विकसित करने का सपना छोड़ कर परमाणु के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहमत होने ही वाला था कि इराक़ल ने युद्ध छेड़ दिया। इस खेल में ट्रंप की मिलीभगत है। ट्रंप अब ईरानियों को तेहरान छोड़ जाने की चेतावनी दे रहे हैं। वह अब खेल को लोकतंत्र स्थापना के नाम पर खेलना चाहते हैं। ईरान के शीर्ष नेता खामेनेई को उन्होंने विलेन घोषित कर दिया है और ईरानी जनता को खामेनेई से मुक्ति दिलाने के बहाने भड़काने की पूरी तैयारी है। इसी के चलते ट्रंप यह जानने का दावा भी कर रहे हैं कि खामेनेई कहाँ छिपे हैं। यह युद्ध अब पूरी तरह प्रोपेगैंडा के आधार पर लड़ा जा रहा है। इसमें पश्चिमपरस्त मीडिया की अहम भागीदारी है। इराक़ल और अमेरिका के दावों को तो बढ़ा-चढ़ा कर बताया-दिखाया जा रहा है। ईरान में हुए नुकसान को ही मिचं मसाला लगा कर बताया जा रहा है जबकि ईरान का प्रतिरोध और इराक़ल में हो रही क्षति की बातें कम करके बताई जा रही हैं। ट्रंप मामले में खालिश नृराकुशती कर रहे हैं, और विश्वसनीय नहीं रहे।

कटाक्ष/सहीराम

फिर मौका है

लो जी, एक बार फिर मौका आ गया वॉर रुकवाने का। यह मौका अमेरिका को तो जी गाहे-बगाहे मिल ही जाता है। आखिर तो वह अमेरिका है। और अमेरिका का राष्ट्रपति अगर ट्रंप हो तो फिर वह मौका न भी मिले तो छीन लेता है। जैसे इधर हमारा पाकिस्तान से जो नफ़ा सा युद्ध हुआ, उसे रोकने का श्रेय उसने न हमें लेने दिया और न ही पाकिस्तान को ही लगी हो। बोला-इसका श्रेय तो मैं ही लूंगा। तुम नहीं लेने दोगे तो मैं जबर्दस्ती लूंगा। शोर मचा दूंगा। हल्ला काट दूंगा। क्या कर लोगे। आखिर तो मैं अमेरिका ही नहीं, ट्रंप भी तो हूँ। कुछ लोग इसे करेला और नीम चढ़ा भी कह सकते हैं। तो अमेरिका को तो यह मौका मिलता ही रहा है। क्योंकि तो वह दुनिया में युद्ध रोकने देता है और न ही चौधराहट छोड़ता है। कोई उसे विश्व दरोगा कहता है, कोई उसे दुनिया का चौधरी कहता है। पता नहीं आखिर वह बला क्या है। लेकिन अब तो यह मौका एक फिर से हमें भी मिल रहा है। एक बार पहले जब रूस-यूक्रेन युद्ध शोकवाने का मौका मिला था तो वह यूक्रेन में फंसे अपने छात्रों के बहाने से मिला था। पता नहीं किसकी नजर लगी कि वह श्रेय हमें मिल नहीं पाया। फिर अभी हम ट्रंप भी तो नहीं हुए कि श्रेय जबर्दस्ती ले लें। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है यह नजर मणिपुर की ही लगी हो। अब उन्हें कौन बताए कि जिस मणिपुर को खुद ही किसी की नजर लगी हो, वह किसी और को क्या नजर लगाएगा भला। फिर भी जलकुकड़ें कहने से बाज नहीं आए कि मणिपुर की मार-काट तो शोकवा नहीं पा रहे। उसके बाद तो खैर हमारा अपना ही पाकिस्तान से युद्ध हो गया। वॉर रुकवाने से वॉर करने तक का सफ़र यूँ रहा। अब इसे मेहरबानी तो किस की कहें, पर एक बार फिर वॉर रुकवाने का मौका मिल रहा है। खैर बहाना एक बार फिर से छात्र ही बन रहे हैं। अब ईरान में भी हमारे छात्र फंसे हुए हैं। जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध शोकवा कर-जैसा कहा गया-उन छात्रों को निकाला गया था, वैसे ही अब इन छात्रों को भी निकाल ही लेना चाहिए। फिर जैसे पुतिन और जेलेंस्की से दोस्ती थी, वैसी ही दोस्ती बीबी-यानी नेतन्याहू और ईरानी नेताओं-से भी है ही। एक से थोड़ी ज्यादा गाढ़ी होगी तो दूसरों से थोड़ी हल्की होगी। दुनिया घूमने का आखिर, इतना फायदा तो होना ही चाहिए। नहीं क्या?



किरान रामनृधदास भावनानी

वै श्विक स्तरपर हर वर्ष विश्व शरणाथी दिवस 20 जून को मनाया जाता है जिसकी प्रतिवर्ष एक थीम होती है,जो 20 जून 2025 की थीम मान्यता के माध्यम से एकजुटता है।असल में,दुनिया भर में एक बड़ी संख्या में शरणाथी रहते हैं। इनके साथ आए दिन प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा जैसी कई चुनौतियों के कारण इनको अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है। जिसके बाद इन सभी को कई देशों में पनाह मिल जाती है। वहीं, कई देशों से इनको निकाल भी दिया जाता है। बेशक इन्हें पनाह मिल जाए, लेकिन वो सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाते।शरणाथी के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इसके साथ ही इस दिन को मनाये जाने का एक अन्य उद्देश्य शरणाथियों की बुरी दुर्दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उनकी समस्याओं का हल करना है,संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणाथी सम्मेलन और इसके प्रोटोकाल 1967, हालाँकि भारत अमेरिका ने इसपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं,परंतु इसके अनुसार शरणाथी सम्मेलन और इसका 1967 प्रोटोकॉल अत्यंत महत्वपूर्ण है शरणाथी दुनियाँ के सबसे कमजोर लोगों में से हैं। यह सम्मेलन और प्रोटोकॉल उनकी सुरक्षा में मदद करता है। वे एकमात्र वैश्विक कानूनी सन्धान हैं जो स्पष्ट रूप से एक शरणाथी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हैं। उनके प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने इसके निकाल दिये जायें कि देश में अन्य विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार के समान मानकों के पात्र हैं और, कई मामलों में,नागरिकों के समान व्यवहार।1951 के कन्वेंशन में कई अधिकार शामिल हैं और यह अपने मेजबान देश के प्रति शरणाथियों के दायित्वों पर भी प्रकाश डालता है। 1951 के कन्वेंशन की आधारशिला गैर-रिफाउलमेंट का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार, एक शरणाथी



प्रमोद भार्गव

दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की जनगणना की अधिसूचना जारी हो गई है। कोविड महामारी के कारण 2021 में होने वाली यह जनगणना अब शुरू होगी। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जातिवार जनगणना कराने की मांग कर रहा था। अचानक मोदी सरकार ने जातिवार जनगणना कराने का फैसला कर दिया है। इसका कारण क्या होगा मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सभी वर्गों की प्रमुख जातियों के साथ उपजातियों की जनगणना के आंकड़े जब सामने आएंगे, तब यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि सैद्धांतिक रूप से जातिगत गणना कराना उचित था या नहीं? ई-बाजार, ई-आवेदन, ई-रेल व बस में आरक्षण ई-भुगतान के बाद अब ई-जनगणना यानी डिजिटल गिनती होगी। इस गिनती में जाति की गिनती भी साथ-साथ होगी। इसमें जन्म और मृत्यु, दोनों ही डिजिटल जनगणना से जुड़े होंगे। हर जन्म के बाद डिजिटल जनगणना खुद ही अद्यतन हो जाएगी और जब किसी की मृत्यु होगी तो उसका नाम खुद ही डाटा से डिलीट

विश्व शरणाथी दिवस : मान्यता के माध्यम से एकजुटता

को उस देश में नहीं लौटाना जाना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। शरणाथियों द्वारा इस सुरक्षा के लिए उचित रूप से खतरा माना जाता है, या विशेष रूप से गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है,उन्हें समुदाय के लिए खतरा माना जाता है। परंतु मैं एडवाकेट किशन राममुखदास भाववाणी गोंदिया महाराष्ट्र, यह मानता हूं कि अभी 1951 सम्मेलन तथा 1967 के प्रोटोकॉल को संशोधन करने की जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि वर्तमान समय में हम अमेरिका- भारत-पाकिस्तान सहित सभी देशों में हो रहे गंभीर दंगों व आतंक विवादों के कारण माहौल दंगों में बदलने की संभावना हो गई है?भारत का ऑपरेशन पुशबैक व अमेरिका का टारगेट@3000 से दंगा भड़क उठा है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे वैश्विक परिपेक्ष में जबरन स्थायी पलायन शरणाथी बनाम भय उत्पीड़न हिंसा व पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन शरणाथी। साथियों बात अगर हम अमेरिका की करें तो वहां भी घुसपैठ का हाल कमोबेश ऐसा ही है। यह जब एक बार घुसपैठिया अंदर आ जाता है तो उसको डिपोर्ट करना भी इसी तरह एक लंबा और विवादस्पद मामला बन जाता है। अमेरिका में लॉस एंजिल्स शूर्यांक और सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ ऐसे शहर हैं,जहाँ अधिकारियों को इन घुसपैठियों से पूछताछ करने या उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति नहीं है। ये शहर डिपोर्ट करने के आदेशों या पुलिस के साथ सहयोग करने से साफ इनकार करते हैं, उन्हें कानून प्रवर्तन के राजनीतिक हथियार के रूप में देखते हैं।जून 2025 की शुरुआत से लॉस एंजिल्स में इसी से जुड़ा एक नाटक चल रहा है। यहाँ घुसपैठियों पर जब एक्शन चालू हुआ तो इसके विरोध में प्रदर्शन होने लगे। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर ऑसू गैस और रबर की गोलियों चलाईं। यहाँ इसके बाद यूनिशन नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, सरकार ने इसके बाद टाइलर 10 कानून के तहत 4,000 नेशनल गार्ड सैनिकों और 700 मरीन को तैनात करके जवाब दिया। इसके बाद तो बवाल और बढ़ा। कई कारों को जला दिया गया, सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया, कई प्रक्रारों को घायल कर दिया गया। इस पूरे बवाल से ट्रंप सरकार की घुसपैठियों को लेकर नीति और किसी शहर को उनके लिए स्वर्ग बनाने की राजनीति माना जा सकता है। इन सब

चक्करों में डिपोंटेशन और भी कठिन हो जाता है। भले ही अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति सख्त सीमा प्रवर्तन और भूमि से अवैध अग्रवासियों को हटाने के लिए जोर दे रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रणाली और कुछ विशिष्ट शहर इससे कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों बात अगर हम भारत की करें तो यहाँ भी वर्तमान में ऑपरेशन पुशबैक चल रहा है। इसके तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का प्रयास हो रहा है। यह कार्रवाई अभी कुछ हजार लोगों तक ही सीमित है।भारतीय फैशन,असल में एक बार जब अवैध प्रवासी किसी देश में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें वह भारत हो, अमेरिका फिर या यूरोप के देश, तो उन्हें वापस भेजना कानूनी अड़चन, राजनीतिक विरोध और एक्टिविज्म का एक चक्रव्यूह बन जाता है। कायदा तो यह होना चाहिए कि किसी देश में अवैध रूप से रहने वालों को उठा कर सीधे वापस भेज दिया जाना चाहिए। हालाँकि, यह लंबी अदालती लड़ाइयों, एक्टिविज्म और कानूनी दाँवपेंच में बदल गया है। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ भारत जैसे देशों में घुसपैठियों को बाहर निकालना मुश्किल का काम है, वहीं पाकिस्तान धड़ाधड़ अफगानिस्तान के लोगों को वापस अपने देशों में भेजने से रोकते हैं। हालाँकि, भारत ने इमेशा पड़ोसी देशों से आने वाले शरणाथियों को मानवीय आधार पर स्वीकार किया है और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया है। भारत का मानना है कि शरणाथी समस्या एक द्विपक्षीय मुद्दा है और स्थिति सामान्य होने पर शरणाथियों को अपने देशों में वापस लौट जाना चाहिए। भारत में शरणाथियों के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, सभी व्यक्तियों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वे भारत के नागरिक हों या नहीं। इसका मतलब है कि शरणाथियों को भी इस अधिकार से सुरक्षा मिलती है, और उन्हें मनमाने ढंग से वापस नहीं भेजा जा सकता है। भारत में

शरणाथी समस्या के समाधान के लिए एक स्पष्ट शरणाथी नीति की आवश्यकता है जो शरणाथियों के प्रबंधन के लिएपारदर्शी और जाबजबादेह व्यवस्था का निर्माण करे। अमेरिका 1951 के अंतर्राष्ट्रीय शरणाथी सम्मेलन में शामिल नहीं है, लेकिन उसने 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, 1967 का प्रोटोकॉल 1951 के सम्मेलन के दायरे को व्यापक बनाता है,इसका मतलब है कि अमेरिका ने शरणाथियों की स्थिति से संबंधित कुछ दायित्वों को स्वीकार किया है, लेकिन सभी दायित्वों की नहीं, 1951 का शरणाथी सम्मेलन शरणाथियों की परिभाषा और उन्हें प्रदान किए जाने वाले अधिकारों की निर्धारित करता है, 1980 का शरणाथी अधिनियम अमेरिकी आब्रजन कानून में शरणाथी की परिभाषा और शरण की प्रक्रिया को शामिल करता है. इस अधिनियम में, अमेरिका ने 1967 के प्रोटोकॉल के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की बात कही है। साथियों बात अगर हम सही अर्थ में शरणाथी दिवस के समर्पित पीड़ितों की करें तो, बता दें कि विश्व शरणाथी दिवस उन लोगों के लिए समर्पित दिन है, जो किसी मजबूरी के कारण अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर होते हैं और वहां पर कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं. दुनियाभर के कई देशों में देखा गया है कि लोग आपदा, बाढ़, किसी महामारी,युद्ध के कारण,हिंसा समेत अन्य कारणों से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर में ऐसे लोगों के मदद और उनके संघर्षों के लिए इस दिन को उनके लिए समर्पित किया है. इतना ही नहीं इन शरणाथी को प्रेरित किया जाता है, वह दूसरे देशों में जाकर खुद के जीवन को दोबारा से शुरू कर सकते हैं. जिससे उन्हें और उनके परिवार को वहां पर नया जीवन मिले और उन्हें जीवन जीने के लिए बेहतर सुविधाएं भी मिल सकें। अतः अगर हम अपरूप पुरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विश्व शरणाथी दिवस 20 जून 2025 - मान्यता के माध्यम से एकजुटता वैश्विक बदलते परिपेक्ष में जबरन स्वाधीन पलायनशरणाथी बनाम भय उत्पीड़न हिंसा व पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन पीड़ित शरणाथी दुनियाँ की बदलती परिस्थितियों से क्या अंतरराष्ट्रीय शरणाथी सम्मेलन 1951व इसके प्रोटोकॉल 1967 के संशोधन की जरूरत नहीं?भारत के ऑपरेशन पुशबैक व अमेरिका के टारगेट@3000 इसके सटीक उदाहरण हैं।

मुद्दा: डिजिटल होगी जाति जनगणना

हो जाएगा। सेंसर रजिस्टर यानी जनगणना में बच्चे के जन्म, माता-पिता, जाति और जन्म स्थान की जानकारी समेत 16 भाषाओं में 36 प्रश्नों के उत्तर दर्ज हो जाएंगे। बालक जब 18 साल का होगा तो खुद ही उसका नाम चुनाव आयोग के पास चला जाएगा। नतीजतन, उसका मतदाता पहचान पत्र बनने के साथ मतदाता सूची में भी नाम स्वयमेव दर्ज हो जाएगा। फिर जब किसी की मौत हो जाएगी तो ऑनलाइन जनगणना के डाटा से उस शख्स का नाम खुद ही डिलीट होी हो जाएगा। इस तरह से जनगणना का डाटा हमेशा खुद अद्यतन होता रहेगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया पर करीब 12000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। डिजिटल जनगणना की घोषणा 1 फरवरी, 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। जनगणना-2021 में नागरिकों को गणना में शामिल होने की एक बेहतर और अनूठी ऑनलाइन सुविधा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना का अधिकार देने के लिए नियमों में परिवर्तन किए हैं। जनगणना (संशोधन), 2022 के अनुसार परंपरागत तरीके से तो जनगणना घर-घर जाकर सरकारी कर्मचारी करेंगे ही, लेकिन अब नागरिक स्व-गणना के माध्यम से भी अनुसूची प्रारूप फार्म सकता है। इसके लिए पूर्व नियमों में 'इलेक्ट्रॉनिक फार्म' शब्द जोड़ा गया है, जो सूचना तकनीकी कानून, 2000 की धारा दो की उपधारा (एक) के खंड आर में दिया गया है। इसके अंतर्गत मीडिया, मैनेटिक, कंप्यूटरजनित माइक्रोचिप या इसी तरह के अन्य उपकरण में तैयार कर भेजी जा संग्रहित की गई

जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में दी गई जानकारी माना जाएगा यानी एनरायड मोबाइल से भी अपनी गिनती दर्ज की जा सकेगी, जो आजकल घर-घर में उपलब्ध है। इस ऑनलाइन प्रविष्टि के अलावा घर-घर जाकर भी जनगणना की जाएगी। गिनती के विकेंद्रीकरण के इस नवाचार से देश जहां 10 साला जनगणना की बौझिल परंपरा से मुक्त होगा वहीं देश के पास प्रति माह प्रत्येक पंचायत स्तर से जीवन व मृत्यु की गणना के सटीक आंकड़े मिलते रहेंगे। जनगणना में निरंतरता इसलिए भी जरूरी है कि देश-दुनिया में जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या लगभग सात सौ करोड़ हो चुकी है। धरती पर जितनी तेजी से मानव समुदायों की आबादी उन्नसर्वी सदी में बढ़ी है, उतनी तेजी से बढ़ोतरी पहले कभी दर्ज नहीं हुई। एक अनुमान के मुताबिक इसवी सन एक में धरती पर कुल आबादी लगभग तीस करोड़ थी। अठारहवीं शताब्दी के अंत में दुनिया की जनसंख्या एक अरब के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई थी। इन शताब्दियों में जन्म दर की मात्रा अधिक होने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर बेहद मंद थी। प्रकृति पर निर्भर गर्भनिरोधकों से दूर और उपचार की आसान-सुलभ पद्धतियों से अनजान स्त्री-पुरुष बच्चे तो खूब पैदा करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर मर जाया करते थे। बीमारियों की पहचान-उपचार से नियंत्रण के चलते बीसवीं शताब्दी के पहले ही तीन दशकों में आबादी दोगुनी होकर करीब पौने दो अरब के आंकड़े को छू गई थी। हरेक दस साल में की जाने वाली जनता-जनार्दन की गिनती में करीब 34 लाख कर्मचारी जुटते हैं। छह



लाख ग्रामों, पांच हजार कस्बों, सैकड़ों नगरों और दर्जनों महानगरों के हवावसियों के द्वार-द्वार दस्तक देकर जनगणना का कार्य करना कर्मचारियों के लिए जटिल होता है। यह काम तब और बौझिल हो जाता है, जब किसी कर्मचारी-दल को उसके स्थनीय दैनंदिन कार्य से दूर कर उसे दूरचल गांव में भेज दिया जाता है। ऐसे हालात में गिनती की जल्दबाजी में वे मानव समूह छूट जाते हैं, जो आजीविका के लिए मूल निवास स्थल से पलायन कर जाते हैं। इन विस्थापितों का जनगणना के समय स्थायी ठिकाना कहाँ है, जनगणना करने आए दल को यह पता लगाना मुश्किल होता है?

Reshaping West Asia's strategic map

The roots of the Iran-Israel standoff lie in the seismic shift of 1979, when the Iranian Revolution overthrew the Shah and birthed a Shia regime with ambitions that aimed to claim a leadership position in the Islamic world. This ideological transformation triggered a sectarian rivalry that rallied other Sunni states to counterbalance Iran's regional influence, the primary one being Saudi Arabia. It was also a time when Arab states were seen to be retreating from their once-strident anti-Zionist positions after repeated military defeats.

The new clergy-led Iranian regime stepped in with a fierce anti-Israel posture. Israel was cast as a symbol of Western-backed oppression—an ideological anathema. Support, over time, for militant groups like Hezbollah (Shia), Hamas, and Islamic Jihad—despite the sectarian diversity—underscores how Iran's strategic opposition to Israel could bridge even Shia-Sunni divides. Iran today is probably more anti-Israel than all the Arab nations put together. For Iran, confrontation with Israel serves three purposes—regime consolidation, assertion of regional influence, and provision of a strategic and ideological counterweight to the Western-aligned Sunni monarchies of the Persian Gulf. The nuclear dimension complicates this further. Iran's nuclear programme, long a subject of global anxiety, is more than just a shield against regime change. It represents a bid to strategically balance Israel, the region's undeclared nuclear power. While Israel remains the most prominent target in Tehran's rhetoric, the implications of an Iranian bomb go well beyond.

The latest Israeli strikes on Iranian nuclear and military infrastructure must be seen in this context, with the idea that Israeli intelligence suspected a few weeks or even days to Iran's overt declaration of nuclear weapon status. However, to be fair, we have had such reports earlier too, including in the context of Iraq two decades ago. Then there is the contingency of Benjamin Netanyahu under the pressure of a pending legal action postponed because of national security contingencies. Many believe the unilateral Israeli initiation of war with Iran is linked to enhancing the contingencies. Israel employed air-launched and long-range missiles against known and suspected nuclear sites, drone facilities, missile depots, and command-and-control nodes. Its ability to damage the Natanz facility, partially above ground, is plausible. But Fordow, buried deep beneath a mountain near Qom, presents a greater challenge. It's fortified beneath layers of rock and concrete, likely beyond the reach of even sophisticated Israeli bunker-busting munitions. Nonetheless, cyber sabotage, electromagnetic disruption and precision strikes on adjoining infrastructure would have happened. With much of Iran's proxy network— from Hezbollah in Lebanon to Houthis in Yemen—disrupted or degraded through prior action, Israel is now systematically targeting Iran's conventional military infrastructure. This would include airbases, radar systems, ballistic missile launchers, drone factories, logistics hubs and military units. Such a strategy, while risky, is motivated by the belief that this is a narrow window of opportunity to impose long-term strategic costs on Iran's ability to project power. Ensuring Iran's proxies do not reconstitute easily will also be a challenge.

The US has not publicly joined the war, but its imprint is unmistakable. Washington's strategic backing and coordination is a force multiplier.

Acid test for India's Look West policy

New Delhi may find it progressively difficult to sustain its policy posture in West Asia amid the Israel-Iran conflict

NDIA often faces unexpected foreign policy and security challenges as collateral fallout of regional conflicts or global crises. The outbreak of an all-out war between Israel and Iran threatens to undo the gains made in pursuing, in parallel, closer political, security and economic relations with the countries of West Asia and the Gulf and with Israel, even while maintaining a relatively cordial relationship with Iran. India has displayed considerable deftness in juggling what could have been competitive relationships. Israel has become a key partner in upgrading India's defence and security capabilities and the value of this partnership was evident in the recent military clash with Pakistan. That the key Gulf countries were themselves seeking a more collaborative relationship with Israel created an opportunity to reinforce, simultaneously, relations with all key players in India's western neighbourhood. This includes the US, which has maintained a strong security presence in the region and serves as the last-resort guarantor. The tacit Indo-US partnership in the Gulf is underscored by India's participation in the I2U2 grouping, which brings together India and Israel, and the UAE and the US in what has been described as the "Quad" in the West. The US Central Command headquarters (Centcom), which is responsible for maintaining security in the West Asian and Gulf region, hosts an Indian liaison officer. The India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) project, which would have established a transport corridor between India and the Gulf on to the port of Haifa in Israel, was based on the expectation of relative peace and stability in this region. One must acknowledge that neither Iran nor Türkiye, both key countries in the region, have been happy about these initiatives, in which they play no role. However, India has been careful to maintain good relations with them. This Look West policy has been successful in promoting India's energy security, in finding expanding markets and investment sources and in ensuring the welfare of the 9 million Indians living and working in the countries of the region. The eruption of the war in Gaza in 2023, Israel's escalating violence and barbarity towards the Palestinian people and the revival of the Palestinian issue as a centrepiece of regional peace and stability has thrown the entire region into turmoil. While India has made



facilities and energy infrastructure. Iran has retaliated with its arsenal of ballistic missiles, some of which have penetrated Israeli defences and caused considerable damage and loss of life. Israel's initial success in being able to launch precision aerial attacks against Iranian targets at will and especially its ability to locate and assassinate virtually the entire senior leadership of Iranian revolutionary guards as well as the armed forces and several nuclear scientists, would have been deeply demoralising for Tehran. It would have also bred a mood of triumphalism and hubris among the Israelis, but they are now surprised at the ability of the Iranians to hit back with unexpected lethality.

The war is in an escalatory phase. It could spread across the region. It has already led to a spike in oil prices, a disruption in trade and transportation and could threaten the large Indian diaspora in the region. India will be paying a heavy price for Israel's reckless action. Does the

partnership with Israel override the need to safeguard our significant stake in regional peace and stability?

Why did Israel unleash this dangerous war with Iran? And what role has the US played in this? Israel would not have embarked on this so-called "Rising Lion" operation without the tacit go-ahead from the US. America has acknowledged that it was aware that this operation was being launched and that is why it ordered non-essential personnel and family members of other personnel deployed in the region to be evacuated. The US has been as determined as Israel in preventing Iran from becoming a nuclear weapon state. It is as convinced as Israel that Iran has been severely weakened by the decimation of its proxies — Hezbollah in Lebanon and the Hamas in Gaza — and the more recent fall of its ally Assad in Syria. Its close ally, Russia, is embroiled in the war against Ukraine, and China is unlikely to go beyond rhetorical support. Several pro-Israel elements in the US have argued that this may be the best opportunity to carry out a military strike to disable Iran's nuclear facilities and even engineer a regime change. While Israel has carried out the initial attacks, it is likely that the US will join in carrying out subsequent and more deadly attacks. It has powerful bunker-busting bombs, which Israel does not, and which could destroy the facilities buried deep underground both at Natanz and Fordow. The US and Israel believe that while Arab and Gulf countries have criticised the attacks against Iran, they would in private welcome the destruction of Iran's nuclear capabilities. Iran has never been as weak as it today since it was engaged in an eight-year-long war with Iraq soon after the founding of the Islamic republic. It is also surprising how deeply the Israeli intelligence has been able to penetrate the highest echelons of the Iranian government. Iran is no doubt very vulnerable. However, it is a large country with a significant population. It is a civilisational state with a strong sense of identity. Its Shia character gives its people the capacity to bear pain and sacrifice that must never be underestimated. Even in its weakened state, it has been able to inflict considerable damage on Israel with its missile attacks.

Parents, teachers must shield kids from e-abuse

It is up to parents and school authorities to inculcate in children a sense of responsibility while exploring social media, and put in place guidelines for usage

The dangers of smartphone usage by the young are showing up in multiple ways—from sleep deprivation to online sexual abuse and exploitation. A study by the Karnataka State Commission for Protection of Child Rights lays bare the growing number of young children ensnared in nets of abuse. It raises concern on their exploitation, and that both parents and teachers are unaware and ill-equipped to handle such situations. Conducted across five districts among those aged 8-18 years, it found that one in six teenagers had connected with strangers online, and one in ten had even met them personally. Gender-wise, 17 percent of boys and 4 percent of girls indulged in such risky behaviour, which is more prevalent in rural areas (12 percent) than urban spaces (9 percent). Worse, 1 percent of children across genders admitted to sharing intimate photos or videos, and 7 percent had shared personal information like addresses with strangers online. The 15-18 age group was the most vulnerable and also aware that they had had unsafe experiences. Instagram accounted for 77 percent of such cases. Only a third of the parents reported these



crimes to the police, while others preferred to close the chapter by deleting the accounts.

While such risky behaviour could be put down to adolescent curiosity, it exposes them to cyberbullying, emotional abuse, blackmail, stalking and sexual exploitation. This could play havoc with young minds, diverting them from

academics and healthy interactions. UNICEF has also flagged the risks of AI-driven technology on digital platforms, and the need to protect young users from manipulative practices, personal data monetisation and exploitative digital marketing. Online child sexual exploitation and abuse is labelled as a global health issue. Youngsters should know the "4Cs of online safety"—regarding content, contact, conduct and commerce. Broadly, what is harmful content, whom to avoid, what to share, and being wary of gambling, phishing and other financial scams. With the pandemic having regularised the use of mobile phones and laptops for study, supervision of screen time needs to be tightened. It is up to parents

and school authorities to inculcate in children a sense of responsibility while exploring social media, and put in place guidelines for usage. Parents and youngsters should ensure they report such crimes to the authorities to enable a systematic crackdown on pervers on the prowl.

Skies clearer, clouds on ground

The numbers say that air travel has become safer in India since the turn of the century. The bigger problem is on the ground, where road and rail accidents claim thousands of lives each year, abetted by systemic failures and a cultural disregard for safety norms

One could be excused for being weighed down by a sustained spell of sadness on account of last week's pointless tragedy of an Air India flight crashing into a college hostel and killing more than 270 people in all. One supposes in the same breath that it's the essence of tragedies—their pointlessness; death without reason. Despite the heavy toll and the sensational nature of the incident, the fact remains that air travel in India has been getting safer. According to the International Civil Aviation Organization, India recorded zero accidents per million departures for scheduled commercial flights in 2023, a marked improvement over the 0.87 accidents per million in 2022. Since 1947, commercial airline accidents in India have claimed a reported 2,173 lives in 52 fatal incidents, with 80 percent of those between 1951 and 2010 attributed to pilot error. These numbers, however, pale against other types of accidents. Perhaps because we are congenitally more tolerant of chaos as a civilisation, deaths from road accidents result in vast numbers of deaths. Tardy observance of traffic rules is only one factor. The state of the roads themselves is fatality-inducing. Mind-numbing numbers of casualties are distributed across road traffic collisions, rail accidents, drownings, fires and industrial mishaps. Data from the National Crime Records Bureau paints a funereal picture. Road traffic collisions are the leading cause of accidental deaths in India, far surpassing others. In 2023, an estimated 1,72,000 people died in road accidents, averaging 474 deaths per day. That's a lot. The NCRB reported a significantly lower

number in some years prior, though. In 2021, for example, the number of fatalities was 1,55,622, with two-wheeler crashes accounting for 69,240 deaths. This kind of situation calls for thorough discussions at the right forums, including parliament. But how many times have MPs raised the issue? Despite improvements in road safety in some surveys, the sheer volume of vehicles—295 million in 2019—and lax observance of rules such as seatbelt and helmet usage, and scant road sense, contribute to the crisis.

India's vast railway network is another terrifying source of mortality. Between 2018 and 2022, rail accidents resulted in 1,07,071 fatalities. Which brings an old nagging question to the fore: why are railway passengers not reasonably insured?

The NCRB recorded 17,993 railway accidents in 2021, a 38 percent increase from 2020, with Maharashtra seeing the highest numbers. Mumbai contributes heavily. An average of seven local train commuters die daily in Mumbai, based on 2023 data reporting 2,590 deaths on the suburban railway network. Only last week, five commuters fell off in a cluster from a speeding local train to their death. Who knew going to work was war? And when was the last time the issue found mention in the assembly? Determining how accidental deaths are increasing exponentially requires nuanced analysis by experts. For aviation, the trend is clearly downward. The 2011-2020 decade saw only two fatal commercial airliner

crashes in India—one in Mangaluru in 2010 and the other in Kozhikode in 2020, compared to seven in the 1991-2000 period. The Ahmedabad crash, while devastating, is an outlier in an otherwise safer aviation sector.



Road accidents, however, show a more complex picture. While the annual death toll remains staggeringly high, the rate of fatalities per 1,00,000 people—16.6 in 2013, as per WHO—has not risen proportionately with the increase in vehicles or population. Initiatives like the Council of Scientific and Industrial Research's online accident reporting portal and road safety audits suggest progress, but the absolute number of deaths remains a public health crisis. Other accidental death categories, such as drownings or industrial incidents, lack sufficient recent data to confirm trends, but historical patterns suggest they remain persistent

challenges. Then there are religious gatherings and pilgrimages where scores die in stampedes. That the gods or godmen, the believers crowd around to have a glance at, have no power to save them from death does not prevent the frequent recurrence of the tragedy. The Maha Kumbh Mela stampede in Prayagraj in January, resulted in at least 30 deaths. But that is the official figure. Reuters reported a higher toll, with a witness counting 39 bodies in the morgue at Moti Lal Nehru Medical College. A BBC report later claimed at least 82 deaths. That these figures vary points to fundamental flaws in the way we assess even the factuality of such incidents. All said, aviation remains the safest mode of travel. Still, the crash exposes vulnerabilities. The official investigation is progressing. But as a lay observer, I do wonder how a six-story college hostel was allowed to come up so close along the airport's take-off path. Critics have argued that India's aviation regulator and airport authorities have been lax, with urban encroachment around airports posing risks. The fact is that India's chaotic urban development—whether it is Mumbai, Bengaluru or Ahmedabad—is innocent of any great rigour in planning. In contrast, road and rail accidents, which claim far more lives annually, suffer from systemic issues: inadequate infrastructure, weak enforcement and a cultural disregard for safety norms. The public and media's focus on the rarer air crashes often overshadows these chronic problems.

Microsoft layoffs: Tech giant to cut thousands of jobs in sales, says report

New Delhi. Microsoft is preparing to cut thousands of jobs, mainly in its sales division, reported Bloomberg. The news of workforce reduction comes as the tech company continues to adjust its workforce while investing more heavily in artificial intelligence. The report, which cites people familiar with the matter, says that the job cuts could be announced as early as next month. This will likely follow the end of Microsoft’s current financial year. While sales teams are expected to be affected the most, the report notes that the layoffs will not be limited to them. The final decision on timing may still change. This round of layoffs follows Microsoft’s earlier job cuts in May, which impacted around 6,000 workers across various departments. Microsoft has been focusing more on AI as it tries to stay ahead in a fast-changing technology landscape. The company is putting more money into data centres and AI research to support growing demand from businesses that are adopting AI tools and services. The report also said that Microsoft has planned capital expenditure of around Rs 6.6 lakh crore (\$80 billion) for the ongoing financial year. A large part of this spending will go into expanding data centre infrastructure. The aim is to reduce pressure on existing facilities that support AI services.

After license, India looks to partner with Starlink on satcom infrastructure, others

CHENNAI. Tata Technologies shares surged approximately 2% in early trade, hitting 7746.10—a clear signal of investor confidence in its global business expansion after being selected by Volvo Cars as a strategic supplier. Although the stock later dipped to 7730.35 by 11 a.m., sector analysts view the Volvo deal as a strong endorsement of Tata Technologies’ credibility with other global original equipment manufacturers (OEMs). The Tata Group company informed stock exchanges today that it has been chosen by Volvo Cars as a strategic supplier, recognizing its capabilities in delivering sustainable solutions for global automotive companies. Volvo Cars—renowned for its leadership in automotive safety and sustainability—is reimagining mobility through electrification, software-defined vehicles (SDVs), and intelligent in-car experiences. This new partnership significantly expands the existing relationship between the two companies. Tata Technologies will now provide enhanced product engineering, embedded software, and product lifecycle management (PLM) services through its global delivery hubs in Gothenburg, India, Romania, and Poland. In its exchange notification, Tata Technologies stated that its expertise in turnkey product engineering and digital transformation will play a broader role in supporting Volvo’s innovation journey. Commenting on the collaboration, Warren Harris, CEO and MD of Tata Technologies, said: “We are delighted by the trust that Volvo Cars has shown in our capabilities by providing newer opportunities to collaborate and scale our relationship.”

Start-up founders get relief on Esops holding



New Delhi. In a move that will offer a major relief to the start-ups founders planning public listing, capital market regulator Sebi has allowed them to hold on to their employees stock ownership plan (Esops) provided they were issued one year before the public issue filing. The regulator has also created a special category for foreign funds to invest in government securities called GS-FPIs and aligned their KYC norms with that of the Reserve Bank. Announcing these decisions and a host of others after a marathon board meeting here this evening, which cleared as many as 19 proposals/amendments to the existing sebi norms on Wednesday, Sebi chairman Tuhin Kanta Pandey said all the 19 decisions have been taken after detailed consultation with the industry and will go a long way to further relax the ease of doing business. “The proposal approved by the Sebi board shall facilitate founders who received ESOP benefits at least one year prior to the filing of IPO papers with the Sebi, to continue holding, and/or exercising such benefits even after being specified as the promoters and the company becoming a listed entity,” the chairman said highlighting that the decisions are part of an overall objective of enhancing the ease of business. The start-up ecosystem has been seeking amendment to the Esop rules as many founders are listed as promoters for an IPO, based on their shareholding including the options which were vested, because public-issue norms require that. This decision is expected to convince start-up founders to come to the public markets, said Pandey, adding however, that an industry proposal for allowing fresh ESOPs benefits to be availed by founders after the listing was not approved by the board. Currently, founders have to be classified as promoters before filing for an IPO, but the hindrance is that the rule also prohibit issuance of Esops to them as promoters. The watchdog said a person who ceased to be an employee after having been identified as a promoter be allowed to continue to hold their Esops, provided those or other benefits were issued one year before the IPO.

Air India cuts 15% of international ops till mid-July citing checks, global unrest

Air India has temporarily cut 15% of its international widebody flights until mid-July due to Middle East tensions, airspace curfews in Europe and East Asia, and increased safety measures following recent disruptions. This comes after the June 12 Ahmedabad plane crash.

New Delhi. Air India has announced a temporary curtailment of its international flight services, reducing operations by 15% on widebody aircraft from now until at least mid-July. Notably, this comes after an Air India flight crash in Ahmedabad on June 12, shortly after takeoff. The airline said that the decision is

aimed at ensuring greater operational stability, better efficiency and minimising passenger inconvenience amid several compounding challenges. In a post on X, Air India wrote, "Due to the geopolitical tensions in the Middle East, night curfew in the airspaces of many countries in Europe and East Asia, the ongoing enhanced safety inspections, and also the necessary cautious approach being taken by the engineering staff and Air India pilots, there have been certain disruptions in our international operations over the last 6 days leading to a total of 83 cancellations." In its statement, the airline also noted that these temporary cuts will also serve to increase the availability of reserve aircraft, allowing for smoother handling of any unplanned issues that may arise. It added that the route curtailment was a "necessary and



measured" step under the current circumstances. Regarding the inconvenience faced by the passengers, the airline wrote on X, "Air India apologises to the passengers affected due to these curtailments, and will inform them in advance and make its best efforts to accommodate them on alternate flights. Passengers will also be offered a choice to reschedule their travel without any cost or to be given a full refund, as per their

choice. The revised schedule of our international services, effective from June 20, 2025, will be shared shortly." Air India also commented on the Ahmedabad crash and said that investigations into the cause of the recent accident are still underway, with authorities working to determine the exact reasons behind the incident. Meanwhile, the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has directed enhanced safety inspections of Air India’s Boeing 787-8 and 787-9 fleet.

It added that of the total 33 aircraft, 26 have already undergone thorough checks and have been cleared to return to service. The remaining aircraft are expected to complete inspections in the coming days. The clearance of the majority of the fleet serves as a strong endorsement of the safety protocols and maintenance standards being upheld, the airline wrote.

Your savings account is quietly robbing you, says financial advisor

Financial advisor Lovish Anand has issued a sharp reality check for Indian savers in a recent LinkedIn post titled: "Your Savings Account Is Quietly Robbing You."

New Delhi. You save diligently. You cut back on luxuries. You park your hard-earned money in a savings account or a fixed deposit, thinking it's the safe and responsible thing to do. But what if that very habit is slowly eating into your wealth? Financial advisor Lovish Anand has issued a sharp reality check for Indian savers in a recent LinkedIn post titled: “Your Savings Account Is Quietly Robbing You.” Anand said most Indians still rely heavily on traditional instruments like savings accounts, fixed deposits, or LIC policies for financial planning. But these tools, he warns, aren’t keeping up with inflation, and in many cases, are actually reducing your purchasing power over time. The disparity between interest rates and inflation is significant, with SBI’s savings account interest rate at just 2.5% while inflation hovers around 5-6%. "SBI's latest interest rate? Just 2.5%," Anand pointed out, "Inflation? Hovering at 5 to 6%. Let that sink in." The impact of this imbalance is stark. Even with

significant savings, such as 10 lakhs, individuals are technically losing money every single year. Anand describes fixed deposits, LICs, and



savings accounts as "safety nets" that can sometimes be "leaky," highlighting that while they offer security, they do not foster wealth creation. Anand suggests moving past outdated financial habits that don’t align with one's long-term goals. "Fixed deposits, LICs, and savings accounts aren't wealth creators," he says. "They're safety nets. And sometimes... they're leaky." He emphasizes, "If your financial plan still revolves around these, you're not just playing it safe,

you're playing it small." To mitigate the erosion of wealth, Anand advocates for a strategic shift based on individual risk appetites. He suggests exploring alternatives like index funds, mutual funds, hybrid funds, and arbitrage funds. "These are low-cost or professionally managed options that can help your money grow instead of gathering dust," he said. Anand's remarks reflect a broader trend towards more dynamic and growth-oriented financial instruments, which offer the potential for better returns compared to traditional savings methods. He asserts, "Your money deserves to grow," and warns against letting it "sit idle while inflation chips away at its value." By embracing newer financial tools tailored to diverse risk profiles, savers can potentially enhance their financial outcomes. The objective is to transition from merely preserving wealth to actively growing it in a way that outpaces inflation and meets personal financial goals.

Household gold holdings value jumps to 56% of GDP at \$2.4 trillion

New Delhi. The value of gold the Indian households are sitting on is as much as 56% of the nominal GDP in FY26 and is also bigger than the bank credit, which is only 55% of the economy, according to a foreign brokerage. The brokerage forecast a further rally in gold, which is already quoting near record highs. The 25,000 tone of gold holding with the Indian households is the world’s largest and represents 14% of the global gold stock and at current prices is worth \$2.4 trillion, Tanvee Gupta Jain, chief economist at UBS Securities India, said in a note. She also said their house view on gold price is that the yellow metal will again

touch \$3500 per ounce in FY26. On April 22, the price had crossed this mark by a notch at \$3501 for an ounce/28.8 grams of gold. “We believe the case for gold has become more compelling in an environment of escalating tariff uncertainty, weak growth, high inflation and lingering geopolitical risks. As most of domestic gold demand is met by imports (87%), higher global gold prices (although we expect softer gold volume demand) imply that our net gold imports could remain high at \$55-60 billion or 1.2% of GDP) in FY26. However, we expect current account deficit to remain manageable on additional buffers

created after the pandemic in the form of services trade surplus and remittance flows” she said. Forecasting for a further rally in gold, which is already quoting near record highs, a foreign brokerage has said the value of the 25,000 tonne gold at \$2.4 trillion that our households sit on is as much as 56% of the nominal GDP in FY26 and is also bigger than the bank credit which is only 55% of the economy. The 25000 tone of gold holding with the households is the world’s largest and represents 14% of the global gold stock and at current prices is worth \$2.4 trillion which is as much as 56% of the FY26 nominal GDP.



1.63%, Infosys fell 1.01%, HCL Technologies declined 0.75%, IndusInd Bank was down 0.60%, and Adani Ports slipped 0.58%. Auto and banking stocks showed early strength while IT companies faced selling pressure as markets opened for Thursday's session. The broader market indices opened with mixed signals as Nifty Midcap fell 0.07%, Nifty Smallcap gained 0.14%, while India VIX dropped 2.38%. Among sectoral indices, several posted gains including Nifty Consumer Durables up 0.58%, Nifty Auto rising 0.44%, Nifty Media adding 0.24%, Nifty Realty gaining 0.22%, Nifty Financial Services up 0.15%, Nifty Private Bank rising 0.15%, and Nifty FMCG advancing 0.04%.

Karnataka plans 10-hour days for tech sector employees: Report

At present, Section 7 of the Karnataka Shops and Commercial Establishments Act, 1961, limits working hours to nine per day, and allows a maximum of 10 hours of overtime in three months.

New Delhi The Karnataka government is planning to increase daily working hours for employees in the information technology (IT) sector, reported the Deccan Herald. The move has been met with strong criticism from trade unions, who say it will hurt workers’ rights and damage work-life balance. At present, Section 7 of the Karnataka Shops and Commercial Establishments Act, 1961, limits working hours to nine per day, and allows a maximum of 10 hours of overtime in three months. The total overtime in this period cannot go beyond 50 hours. However, under the government’s new proposal, the

maximum working hours would be raised to 10 per day, with overtime going up to 12 hours per day. The total overtime allowed in three months would also be increased from 50 to 144 hours.

SIMILAR MOVE IN ANDHRA PRADESH

The Karnataka government’s proposal follows a similar decision taken in Andhra Pradesh, where the TDP-led NDA government recently allowed companies to increase the daily working hours from nine to 10. The change was made as part of the state’s efforts to attract investment and make doing business easier. Andhra Pradesh’s Information and Public Relations Minister, K Parthasarathy, said that the state wants to make labour laws more friendly for both workers and companies. He also said that women, who were earlier not allowed to work at night, can now do so with certain safety rules like consent, transport, security, and proper lighting at the workplace. The minister added, “When you work extra, income will increase. By these rules,



women can work in the formal sector. They empower women economically and promote gender inclusion and industrial growth.” But the move has also seen opposition. CPI state secretary K Ramakrishna said that the changes in labour laws are against the interest of workers and benefit companies more than employees.

STRONG OPPOSITION FROM TRADE UNIONS IN KARNATAKA

Several trade unions in Karnataka have opposed the government’s reported plan to extend working hours. On Wednesday, the state Labour Department held a meeting with representatives from the

industry and trade unions to discuss the possible amendment to the law. The Karnataka State IT/ITeS Employees Union (KITU) took part in the meeting and clearly opposed the idea. KITU called the proposal a form of “modern-day slavery” and said it would harm workers’ health, work-life balance, and job security. The union appealed to all employees in the sector to stand together against the proposed changes. KITU leaders Suhas Adiga and Lenil Babu, who attended the meeting, said the law already allows up to 10 working hours per day including overtime. They warned that the amendment would make 12-hour shifts legal and encourage companies to introduce a two-shift system. This, they said, could lead to job cuts and increased pressure on workers. Adiga said, “The government is trying to normalise inhuman working conditions. This change is not about improving productivity—it is about keeping corporate heads happy by turning human beings into machines.”

Huge blow to Indian diplomacy: Congress slams Centre after Trump-Munir meet

Congress general secretary in-charge of communications Jairam Ramesh said Field Marshal Asim Munir is not the Head of State or Head of government of Pakistan and is the Chief of Army Staff, yet he gets invited by Trump for lunch and receives much praise.

New Delhi. The Congress on Thursday attacked the government after US President Donald Trump hosted Pakistan Army Chief Asim Munir for lunch, saying it is a "huge blow" to Indian diplomacy.

Congress general secretary in-charge of communications Jairam Ramesh said Field Marshal Asim Munir is not the Head of State or Head of government of Pakistan and is the Chief of Army Staff, yet he gets invited by Trump for lunch and receives much praise.

"This is the same man whose atrocious and inflammatory remarks formed the immediate backdrop to the brutal Pahalgalam terror attacks orchestrated by the establishment over which he presides," Ramesh said on X. "It is a huge blow to Indian diplomacy (and huglomacy too)," he said, taking a swipe at Prime Minister Narendra Modi.

The Congress has been taking swipes at Modi, giving "hugs" to foreign heads of state during his meetings with them at international or bilateral engagements, using the term "huglomacy" for it.

Meanwhile, Trump has said the two very smart leaders of India and Pakistan decided not to continue a war that could have turned nuclear, a first in weeks. He did not claim credit for



stopping hostilities between the two neighbouring nations. Trump made the remarks while speaking to the media in the Oval Office after hosting Munir for lunch at the White House on Wednesday.

Trump also said he was honoured to meet Munir.

When asked if Iran was discussed in his meeting with Munir, Trump said: "Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad for Israel.

They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me.

"The reason I had him here is I want to thank him for not going into the war, ending the war. And I want to say, as you know, Prime Minister Modi just left a little while ago, and we're working on a trade deal with India. We're working on a trade deal with Pakistan" the president said.

"They were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him. And I'm so happy that two smart people, plus, you know, people on their staff too, but two smart people, two very smart people, decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big, big nuclear powers, and they decided that," he said.

Ghazipur mandi: Filth, feathers and living hell



NEW DELHI. At just past 3 am, the first truck arrives—its towering stack of wire crates squealing and shaking under the weight of thousands of live chickens.

The Ghazipur poultry market, a key hub for the wholesale poultry trade in the capital, is already awake. Flashlights dart in the darkness, middlemen shout prices and buyers elbow through narrow, slippery lanes to claim their stock before daybreak. By sunrise, the stench of blood and decay hangs thick in the air. Kites circle low overhead, hoping for scraps. Stray dogs scavenge around heaps of discarded feathers, entrails and bones.

In gumboots slick with muck, workers pull birds from cramped cages and slit their throats in swift, practised motions. The viscera is tossed into handcarts, blood swept away with brooms and trickling water, forming crimson puddles that run into open drains.

Photography is strictly prohibited and women are barred from entering. Yet residents of nearby colonies complain that the stench spreads across several streets. The adjacent drain, they say, turns red every morning. Outside the market gate, sellers have illegally constructed tin-shed stalls, taking over the space above the drain. The market rarely sees proper cleaning and during rain, pools of filthy water collect in every corner, stagnating for days. Technically, the slaughter lines operate on land owned by the Delhi Agricultural Marketing Board (DAMB). But in practice, much of what goes on at Ghazipur violates national regulations for animal slaughter. These rules require hygienic handling of blood and offal, hand-washing stations, tool sterilisers and closed drainage systems. Eyewitnesses and repeated inspections confirm: Ghazipur has none of these.

Supreme Court directs cops to ensure safety of minor seeking marriage annulment

NEW DELHI. The Supreme Court on Wednesday in its interim order directed the Bihar director general of police (DGP) and the Delhi police commissioner to provide adequate security to a minor girl who was allegedly forced into a marriage with a contractor, and is now seeking its annulment after escaping from her in-laws' house. A bench of Justices Ujjal Bhuyan and Manmohan also directed the senior police officers to ensure that no harm is caused to her or her friend who held her escape. The court also sought a status report from the police on the next date of hearing on July 15.

In her plea, the girl claimed to have been forcibly married to Bihar-based contractor Jai Shankar on December 9, 2024, when she was 16 and a half years old, towards the repayment of the debts owed by her parents. Alleging physical abuse by the 33-year-old man, she also sought the annulment of her marriage with him under the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.

"Her husband, who is a civil contractor, claimed that the petitioner's parents were indebted to them and she would have to continue in the marriage rather than go for further studies to pursue her dream of becoming a teacher or a lawyer," her plea said. The girl also claimed that she was on the run with a friend, and feared for their lives if they returned to Bihar. She said she was sent away immediately after the wedding ceremony, even though her Class 10 board examinations were due to start.

ED raids 37 locations in Delhi over Rs 2,000 crore classroom construction scam



NEW DELHI. The Enforcement Directorate (ED) on Wednesday conducted raids under provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) at multiple locations in the city in connection with its probe into an alleged Rs 2,000 crore classroom construction scam, which allegedly took place during the previous AAP government.

The ED's action has come after it recently registered a case under criminal provisions of PMLA after taking cognisance of an Anti-Corruption Branch (ACB) FIR with regard to the alleged scam. At least 37 premises of private entities linked to the case have been raided by the ED officials.

In its FIR on April 30, ACB has named former ministers Manish Sisodia and Satyendar Jain and a few AAP leaders. The FIR alleged that financial irregularities worth Rs 2,000 crore were done in the construction of over 12,000 classrooms in government schools between 2015-16 and 2022-23. The sources said the ED in its Enforcement Case Information Report (ECIR), equivalent to a police FIR, has also named the same persons. AAP accused the BJP was using the ACB as a "tool" to target its leaders. Sisodia had held the finance and education portfolios in the AAP government and Jain was in-charge of PWD and some other departments.

IMD approves cloud seeding pilot project

NEW DELHI. The India Meteorological Department (IMD) has approved Delhi's pilot project on cloud seeding aimed at mitigating air pollution and all the preparations are complete, Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said on Wednesday.

He said the cloud-seeding flights will take off once favourable weather conditions -- particularly the presence of moisture-laden clouds -- are observed. "All major permissions have been secured. Only minor operational formalities -- such as final flight clearance -- are pending. All preparations are complete. Now we are just waiting for the right clouds to appear. The moment the weather cooperates, Delhi will witness its first artificial rain," Sirsa said. The minister said that the pilot project reflects the government's commitment to clean air. "When we say 'Right to Clean Air', we mean it. From anti-smog guns and sprinklers to strict dust mitigation at construction sites, we are pushing every boundary -- and now even the skies -- for our people," he said. The project, titled 'Technology Demonstration and Evaluation of Cloud Seeding as an Alternative for Delhi NCR Pollution Mitigation', will be executed under the leadership of IIT Kanpur, which will oversee the scientific, technical and operational aspects of the effort. Five aircraft-based sorties are planned over low-security zones in northwest and outer Delhi. These sorties, each lasting around 90 minutes and covering approximately 100 square kilometres, will deploy a custom cloud-seeding mixture using flare-based systems mounted on specially equipped Cessna aircraft. The formulation, developed by IIT Kanpur, includes nanoparticles of silver iodide, iodised salt and rock salt. The IMD will provide real-time meteorological data, including cloud type, altitude, wind direction and dew point to assist with flight planning. The seeding will target Nimbostratus clouds located between 500 and 6,000 metres above ground level, with moisture levels of at least 50 per cent. To assess effectiveness, Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations will track real-time changes in PM2.5 and PM10 levels in and around the seeding zones.

Brass tree, silver pot, paintings: PM's gifts to G7 leaders echo incredible India

A look at what Prime Minister Narendra Modi presented to world leaders at the G7 Summit in Canada last weekend.

New Delhi. As PM Narendra Modi met world leaders during the G7 Summit in Canada, which was held over the weekend, he gifted them a variety of art and craft pieces representing diverse Indian traditions. The gifts for the world leaders were sourced from various parts of the country. Let's explore the unique gifts presented to each leader and the rich cultural heritage behind these handcrafted works.

Canadian Prime Minister Mark Carney

PM Modi gifted Canadian Prime Minister Mark Carney a handcrafted Brass Bodhi Tree during the G7 Summit in Canada. This intricate sculpture from Bihar represents the sacred tree where Buddha attained



enlightenment, symbolising wisdom, peace and spiritual awakening.

French President Emmanuel Macron

Emmanuel Macron received a handcrafted Dokra Nandi sculpture from Tamil Nadu from PM Modi during the G7 Summit in Canada. Made using the ancient lost-wax

technique, the sculpture depicts Nandi, Lord Shiva's sacred bull, featuring intricate open latticework and a vibrant red saddle that highlights traditional Indian metal artistry.

Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo

PM Modi gifted Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo a traditional Warli painting during the G7 Summit in Canada. Originating from Maharashtra's Warli tribe, this folk art uses simple white rice paste designs on mud backgrounds to depict everyday village life, featuring scenes like farming, dancing and celebrations, symbolising community and tradition.

Fire officials, cops among 10 eyewitnesses who saw cash at Justice Varma's house

New Delhi. A Supreme Court-appointed inquiry panel has, for the first time, named the 10 eyewitnesses who saw large quantities of cash inside the store room of Justice Yashwant Varma's official residence in Delhi.

The list includes fire officials, police officers, and personnel from the child rights body: Ankit Schwag, Pradeep Kumar, Manoj Mehlaawat, Bhanwar Singh, Pravindra Malik, and Suman Kumar — all officers from the Delhi Fire Service (DFS); Rajesh Kumar and Umesh Malik from Tughlaq Road police station; Roop Chand, a head constable; and Sunil Kumar, an officer from the Indian Commission for Protection of Child Rights (ICPCR).

The panel found that these eyewitnesses saw stacks of currency notes — reportedly piled 1.5 feet high — in the aftermath of a fire at the judge's residence in March. One witness described being "shocked and surprised" by the sheer volume of

cash, saying it was unlike anything he had ever seen.

Despite the discovery, Justice Varma made no effort to report the matter to police or judicial authorities, the panel



noted. "No plausible explanation has been given. The judge's claim of lack of knowledge is unbelievable," it said. The panel also flagged what it called "unnatural conduct" by the judge, highlighting how the store room — access to which was exclusively controlled by Justice Varma and his

family — was later cleaned out and the cash disappeared. Visual evidence reportedly showed some notes were half-burnt.

Rejecting Justice Varma's defence that the entire episode was a conspiracy to malign him, the inquiry committee stated: "Currency notes were seen by multiple people and recorded in real time. It is implausible they were planted to frame him."

The committee concluded there was "sufficient substance" in the allegations against the Allahabad High Court judge and has recommended his removal. Justice Varma, who was transferred back to the Allahabad High Court following the incident, has not been allotted any judicial work since. He has neither resigned nor taken voluntary retirement and continues to claim the process against him is "fundamentally unjust."

Air India black box damaged, to be sent to US to decode crash mystery: Report

Ahmedabad plane crash: Presently, India is not equipped to extract data from black boxes that have sustained heavy damage. The temperature in and around the crash site reached about 1,000 degrees Celsius.

New Delhi. India is likely to send the black box recovered from the ill-fated Air India flight AI 171, which crashed in Ahmedabad last week, to the United States for data recovery as the recorder sustained heavy external damage due to the fire, a report in Economic Times said. Presently, India is not equipped to extract data from black boxes that have sustained

heavy damage. Thus, according to the report, the Flight Data Recorder (FDR) will be sent to the Washington-based laboratory of the National Safety Transport Board (NTSB) for analysis.

The report will then be shared with the government's Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB), which is probing the horrific crash.

The report said the time to extract data from the black box could range from days to months, depending on the extent of damage.

IMPORTANCE OF BLACK BOX

Last week, the London-bound Air India flight, a Boeing 787 Dreamliner, crashed into the BJ Medical College hostel building in Ahmedabad within seconds of take-off. The tragedy left 274 people, including 241

passengers and crew on board and over two dozen others on the ground, dead. Such was the intensity that the temperature in and around the crash site reached about



1,000 degrees Celsius. This probably explains why the black box, despite being designed to survive extreme conditions, suffered such extensive damage.

The AAIB, which has been given three months to complete the probe, recovered the cockpit voice recorder (CVR) as well as the flight data recorder (FDR) two days after the crash.

The CVR, which captures audio from the cockpit, including pilot conversations, and FDR collectively form what is known as the "black box".

Decoding the black box is significant as it would provide an in-depth insight into what led to the crash and the moments before the tragedy itself.

While the exact reason behind the crash will only be known after decoding the black box, an aviation expert has suggested dual engine failure as a possible cause.

Former US Navy pilot Captain Steve Scheibner, in an interview with India Today, suggested that the deployment of the ram air turbine (RAT) shortly after takeoff pointed to a dual engine failure.

NEWS BOX

Early humans survived in a range of extreme environments before global migration, study says

WASHINGTON: Humans are the only animal that lives in virtually every possible environment, from rainforests to deserts to tundra.

This adaptability is a skill that long predates the modern age. According to a new study published Wednesday in Nature, ancient Homo sapiens developed the flexibility to survive by finding food and other resources in a wide variety of difficult habitats before they dispersed from Africa about 50,000 years ago.“Our superpower is that we are ecosystem generalists,” said Eleanor Scerri, an evolutionary archaeologist at the Max Planck Institute of Geoanthropology in Jena, Germany.

Our species first evolved in Africa around 300,000 years ago. While prior fossil finds show some groups made early forays outside the continent, lasting human settlements in other parts of the world didn’t happen until a series of migrations around 50,000 years ago.“What was different about the circumstance of the migrations that succeeded — why were humans ready this time?” said study co-author Emily Hallett, an archaeologist at Loyola University Chicago.Earlier theories held that Stone Age humans might have made a single important technological advance or developed a new way of sharing information, but researchers haven’t found evidence to back that up.This study took a different approach by looking at the trait of flexibility itself.

The scientists assembled a database of archaeological sites showing human presence across Africa from 120,000 to 14,000 years ago. For each site, researchers modeled what the local climate would have been like during the time periods that ancient humans lived there.“There was a really sharp change in the range of habitats that humans were using starting around 70,000 years ago,” Hallett said. “We saw a really clear signal that humans were living in more challenging and more extreme environments.”

While humans had long survived in savanna and forests, they shifted into everything from dense rainforests to arid deserts in the period leading up to 50,000 years ago, developing what Hallett called an “ecological flexibility that let them succeed.”

Congo, Rwanda to ink peace deal on June 27 in push to end eastern Congo fighting

DAKAR. Congo and Rwanda will sign a peace agreement in Washington on June 27, a joint press release from the nations and the US State Department said Wednesday. Both countries have agreed to the terms of the deal aimed at ending fighting in eastern Congo.Congo has accused Rwanda of backing M23 rebels in the east of the country. UN experts say the rebels are supported by about 4,000 troops from the neighboring nation.The decades-long conflict escalated in January, when the M23 rebels advanced and seized the strategic Congolese city of Goma, followed by the town of Bukavu in February.

The draft agreement includes "provisions on respect for territorial integrity and a prohibition of hostilities; disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups," a joint statement said.The agreement that will be signed also includes a commitment to respecting territorial integrity and the conditional integration of non-state armed groups. Both countries have in the past held peace talks that have largely stalled, including talks hosted by Qatar.Corneille Nangaa, leader of the Congo River Alliance, a coalition of rebel groups, told The Associated Press in April that international sanctions and Congo’s proposed minerals deal with the United States in search of peace would not stop the fighting.M23 is one of about 100 armed groups that have been vying for a foothold in mineral-rich eastern Congo near the border with Rwanda. The conflict has created one of the world’s worst humanitarian crises and has displaced more than 7 million people.

Putin says Russia could help broker a deal between Iran and Israel

ST. PETERSBURG, RUSSIA. Russian President Vladimir Putin offered Wednesday to help mediate an end to the conflict between Israel and Iran, suggesting Moscow could help negotiate a settlement that could allow Tehran to pursue a peaceful atomic program while assuaging Israeli security concerns.

Speaking to senior news leaders of international news agencies, Putin noted that "it's a delicate issue," but added that "in my view, a solution could be found."

Asked how Russia would react if Israel kills Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, Putin refused to answer, saying that "I don't even want to discuss such a possibility."Khamenei has rejected US calls for surrender in the face of more Israeli strikes and warned that any military involvement by the Americans would cause "irreparable damage to them."Putin said he shared Moscow's proposals with Iran, Israel and the United States."We are not imposing anything on anyone; we are simply talking about how we see a possible way out of the situation. But the decision, of course, is up to the political leadership of all these countries, primarily Iran and Israel," he said.Russia has maintained a delicate balancing act in the Middle East for decades, trying to navigate its warm relations with Israel even as it developed strong economic and military ties with Iran, a policy that could allow Moscow to play power broker.Putin's comments follow a mediation offer that he made in a call with U.S. President Donald Trump last weekend.Trump said Wednesday that he told Putin to stay focused on finding an endgame to his own conflict with Ukraine."I said, 'Do me a favor, mediate your own,'" Trump said he told Putin. "I said, 'Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later.'

Homeland insecurity: Expelled Afghans seek swift return to

Since April and a renewed deportation drive, some 200,000 Afghans have spilled over the two main border crossings from Pakistan, entering on trucks loaded with hastily packed belongings.

PESHAWAR. Pakistan says it has expelled more than a million Afghans in the past two years, yet many have quickly attempted to return -- preferring to take their chances dodging the law than struggle for existence in a homeland some had never even seen before."Going back there would be sentencing my family to death," said Hayatullah, a 46-year-old Afghan deported via the Torkham border crossing in Khyber Pakhtunkhwa province in early 2024.

Since April and a renewed deportation drive, some 200,000 Afghans have spilled over the two main border crossings from Pakistan, entering on trucks loaded with hastily packed belongings. But they carry little hope of starting over in the impoverished country, where girls are banned from school after primary level.

Hayatullah, a pseudonym, returned to Pakistan a month after being deported, travelling around 800 kilometres south to the Chaman border crossing in Balochistan, because for him, life in Afghanistan "had come to a standstill."He paid a bribe to cross the Chaman frontier, "like all the day labourers who regularly travel across the border to work on the other side."His wife and three children -- including daughters, aged 16 and 18, who would be denied education in Afghanistan -- had managed to avoid arrest and deportation.

Hayatullah moved the family to Peshawar, the capital of Khyber Pakhtunkhwa and a



region mostly populated by Pashtuns -- the largest ethnic group in Afghanistan. "Compared to Islamabad, the police here don't harass us as much," he said.

The only province governed by the opposition party of former Prime Minister Imran Khan -- who is now in prison and in open conflict with the federal government - - Khyber Pakhtunkhwa is considered a refuge of relative security for Afghans.

Samad Khan, a 38-year-old Afghan who also spoke using a pseudonym, also chose to relocate his family to Peshawar. Born in

eastern Pakistan's Lahore city, he set foot in Afghanistan for the first time on April 22 -- the day he was deported."We have no relatives in Afghanistan, and there's no sign of life. There's no work, no income, and the Taliban are extremely strict," he said.

At first, Khan tried to fin work in a country where 85 percent of the population lives on less than one dollar a day, but after a few weeks he instead found a way back to Pakistan. "I paid 50,000 rupees (around \$180) to an Afghan truck driver," he said, using one of his Pakistani employees' ID cards to cross the border.

Khan rushed back to Lahore to bundle his belongings and wife and two children -- who had been left behind -- into a vehicle, and moved to Peshawar."I started a second-hand shoe business with the support of a friend. The police here don't harass us like they do in Lahore, and the overall environment is much better," he told AFP.

In a first, Trump says leaders of India and Pakistan 'decided' to stop conflict

For the first time in weeks, Trump did not claim credit for stopping India-Pakistan tensions after earlier saying trade pressure helped avert a military conflict.

EW YORK/WASHINGTON. US President Donald Trump said the two "very smart" leaders of India and Pakistan "decided" not to continue a war that could have turned nuclear, the first time in weeks he did not credit himself for stopping of hostilities between the two neighbouring nations.

Trump made the remarks while speaking to the media in the Oval Office after hosting Pakistan's Chief of Army Staff, Asim Munir, for lunch at the White House on Wednesday.Trump said he was "honoured" to meet Munir.When asked if Iran was discussed in his

meeting with Munir, Trump said: "Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually,



but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me.""The reason I had him here, I want to thank him for not going into the war, ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left a little while ago, and we're working on a trade deal with India. We're working on a

trade deal with Pakistan," the president said."They were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him. And I'm so happy that two smart people, plus you know, people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big, big nuclear powers, and they decided."This is the first time in weeks when Trump did not take credit for stopping the military conflict between India and Pakistan.Since May 10, when India and Pakistan decided to stop the military conflict, Trump has repeatedly claimed on multiple occasions that he "helped settle" tensions between the two countries and that he told the nuclear-armed South Asian neighbours that America would do a "lot of trade" with them if they stopped the conflict.

Myanmar's Aung San Suu Kyi marks 80th in junta jail

YANGON, Myanmar's deposed democratic leader Aung San Suu Kyi marked her 80th birthday in junta detention on Thursday, serving a raft of sentences set to last the rest of her life.Suu Kyi was the figurehead of Myanmar's decade-long democratic thaw, becoming de facto leader as it opened up from military rule.But as the generals snatched back power in a 2021 coup, she was locked up on charges ranging from corruption to breaching Covid-19 pandemic restrictions and is serving a 27-year sentence.It will be hard to be celebrating at the moment," said her 47-year-old son Kim Aris from the UK.

"We've learned to endure whe it's been going on so long."He is running 80 kilometres (50 miles) over the eight days leading up to her birthday, and has collected over 80,000 well-wishing video messages for his mother.But Suu Kyi will not see them, sequestered in Myanmar's sprawling capital Naypyidaw from where the military directs a civil war against guerilla



fighters.Aris said he has heard from his mother only once via letter two years ago since she was imprisoned.

"We have no idea what condition she's in," he said.While she remains hugely popular in the majority Buddhist country, her status as a democracy icon abroad collapsed before the military takeover after she defended the generals in their crackdown against the Rohingya Muslim minority.Hundreds of thousands were sent fleeing to neighbouring Bangladesh under her rule, though some argued she was powerless against the lingering

influence of Myanmar's military.Nonetheless institutions and figures that once showered Suu Kyi with awards rapidly distanced themselves, and her second round of imprisonment has received far less international attention.Suu Kyi, the daughter of Myanmar independence hero Aung San, became a champion of democracy almost by accident.After spending much of her youth abroad, she returned in 1988 to nurse her sick mother but began leading anti-military protests crushed by a crackdownShe was locked up for 15 years, most of it in her family's Yangon lakeside mansion where she still drew crowds for speeches over the boundary wall.The military offered freedom if she went into exile but her poised refusal thrust her into the spotlight and won her the 1991 Nobel Peace Prize.This time, she disappeared from the public eye on the eve of the coup.

Hospital in southern Israel hit by Iranian missile; Israel strikes Arak heavy water reactor

Iranian state TV reported the attack on the Arak site, saying there was “no radiation danger whatsoever.”

TELAVIV. An Iranian missile slammed into the main hospital in southern Israel early Thursday, wounding people and causing “extensive damage," according to the medical facility. Israeli media aired footage of blown-out windows and heavy black smoke.Separate Iranian strikes hit a high-rise apartment building in Tel Aviv and other sites in central Israel. At least 40 people were wounded, according to Israel's Magen David Adom rescue service.

Israel, meanwhile, carried out strikes on Iran's Arak heavy water reactor, its latest attack on Iran's sprawling nuclear program, on the seventh day of a conflict that began with a surprise wave of Israeli airstrikes targeting military sites, senior officers and

nuclear scientists.Iran has fired hundreds of missiles and drones at Israel, though most have been shot down by Israel's multi-tiered air defenses, which detect incoming fire and shoot down missiles heading toward population centers and critical infrastructure. Israeli officials acknowledge it is imperfect.

The missile hit the Soroka Medical Center, which has over 1,000 beds and provides services to the approximately one million residents of Israel’s south. A hospital statement said several parts of the medical center were damaged and that the emergency room was treating several minor injuries. The hospital was closed to all new patients except for life-threatening cases.Many hospitals in Israel activated emergency plans in the past week, converting underground parking to hospital floors and move patients underground, especially those who are on ventilators or are difficult to move quickly.No radiation danger’ after strike on reactorIranian state TV, meanwhile, reported the attack on the Arak site, saying

there was “no radiation danger whatsoever.”

An Iranian state television reporter, speaking live in the nearby town of Khondab, said the facility had been evacuated and there



was no damage to civilian areas around the reactor.Israel had warned earlier Thursday morning it would attack the facility and urged the public to flee the area. The Israeli military said Thursday’s round of airstrikes targeted Tehran and other areas of Iran, without elaborating.The strikes came a day after Iran’s supreme leader rejected US calls for surrender and warned that any military involvement by the Americans would cause “irreparable damage to them.”

Israel had lifted some restrictions on daily life Wednesday, suggesting the missile threat from Iran on its territory was easing.

Already, Israel’s campaign has targeted Iran’s enrichment site at Natanz, centrifuge workshops around Tehran and a nuclear site in Isfahan. Its strikes have also killed top generals and nuclear scientists.

A Washington-based Iranian human rights group said at least 639 people, including 263 civilians, have been killed in Iran and more than 1,300 wounded. In retaliation, Iran has fired some 400 missiles and hundreds of drones, killing at least 24 people in Israel and wounding hundreds.

Arak had been redesigned to address nuclear concerns

The Arak heavy water reactor is 250 kilometers (155 miles) southwest of Tehran. Heavy water helps cool nuclear reactors, but it produces plutonium as a byproduct that can potentially be used in nuclear weapons. That would provide Iran another path to the bomb beyond enriched uranium, should it choose to pursue the weapon.



NEWS BOX

India start new era without Kohli and Rohit against England

LONDON. Shubman Gill will be in the spotlight as a new-look India, without star batsmen Virat Kohli and Rohit Sharma, bid to end their 18-year wait for a Test series win in England.Gill succeeded Rohit as captain after the latter announced his retirement from Test cricket last month.Just days later, Kohli said he was bowing out of red-ball internationals as well.Gill also has the additional responsibility of filling Kohli's shoes at number four in the batting order.

India vice-captain Rishabh Pant on Wednesday revealed that was where his new skipper would bat in the first of a five-Test series against England starting at Headingley on Friday.The 25-year-old Gill has a modest Test batting average of 35 in 32 matches, a figure that drops to 29 in away games and declines even further to under 15 in three matches in England.India's number four position has been dominated during the past three decades by all-time batting great Sachin Tendulkar and Kohli, who in that specific position scored 21,056 runs between them in



278 Tests.Gill's first challenge will be ensuring the demands of captaincy don't detract from his batting in England, where India have won just three Test series -- in 1971, 1986 and 2007.Thus far Gill has made all the right noises, saying last month: "I believe in leading by example -- not just by performance, but, I think, off the field by discipline and hard work."He will have the ebullient Pant to lean on after the wicketkeeper-batsman's return from a life-threatening car crash in 2022, while opener Yashvi Jaiswal is one of the game's rising stars.But it is not just in batting where India -- who have had limited warm-up time in England -- must cope without stalwart performers.Jasprit Bumrah is arguably the best all-format bowler in world cricket at present but, following a back injury lay-off, the quick may only play in three of the five Tests given the tight schedule.

Veteran off-spinner Ravichandran Ashwin has retired from Test cricket, while experienced Mohammed Shami, not fully fit following ankle surgery last year, has been omitted.If there are concerns about India's ability to take the 20 wickets they need to win a match, those doubts apply to England as well.

WTC 2025-27: Australia play most Tests, Sri Lanka least

New Delhi. The new cycle of the World Test Championship has already begun, just days after South Africa were crowned as the champions of the third edition of the tournament. South Africa's win was seen as a story of incredible grit and perseverance, given they had given up hope on the competition midway through the cycle.Inspired by Aiden Markram's sensational 4th innings hundred and two gritty knocks from captain Temba Bavuma, South Africa beat the mighty Australians, who were favourites to clinch the title.The victory was seen as refreshing from a neutral perspective, as fans saw the result as a win for Test cricket, as the South African team came



together for a sensational run in the red-ball format, eventually breaking their 27-year wait for an ICC title.However, there was one thing that laser-eyed fans could not ignore. It was the number of Test matches that South Africa played in their WTC cycle.

South Africa reached the summit clash of the WTC 2025 by playing just 12 Test matches. This was the lowest among all teams in the tournament. In comparison, England played 22, Australia and India 19, and New Zealand and Pakistan 14.It did not sit well with many fans that South Africa did not play Australia and England en route to the finals and only played 2 matches at home against India. The argument was that India, Australia, and England play 5 matches against each other, meaning that they compete against tougher opposition more frequently.On that note, here's the complete breakdown of matches that teams will be playing in the WTC cycle. It needs to be noted that these fixtures were already agreed in advance with the FTP — ICC's Future Tours Programme.

Jose Mourinho vs Turkish FA: Fenerbahce demand investigation after leaked texts

- Fenerbahce demand investigation of the Turkish disciplinary authority
- Jose Mourinho was allegedly targetted by the Turkish FA
- Mourinho has been critical of the Turkish referees in the league

Noida. Turkish football club, Fenerbahe have released a statement demanding an investigation into the alleged leaked text messages by the Turkish FA, which involve hostile statements being made about the club and their manager, Jose Mourinho.The club released their statement on X, where they want an explanation regarding the alleged leaked text messages from the members of the Professional Football Disciplinary Board (PFDK), which were targeting the club impartially.Various reports claim that the board members had some of their messages leaked on the internet, and the conversations allegedly included the President implying



that “We will make him pay for this next season. He has been tolerated too much”. Additionally reports from The Mirror, also suggest that the members of the Turkish Football Federation, including the club president, Celal Nuri Demirturk have resigned as well.A club spokesperson was reportedly quoted as saying, “Our club has made an official application to the Turkish

Football Federation in response to the correspondence that has been made public today and is claimed to belong to members of the Professional Football Disciplinary Board".Mourinho made the sensational switch to the Turkish club back in June, the previous year, following his three-year stint with the Serie A side, Roma.During his time in Turkey, the Portuguese manager has often

found himself in the middle of controversy across several incidents. One of the major incidents was when rivals, Galatasaray accused Mourinho of making racist comments which prompted the Fenerbahce manager to hit back by suing the club for wrongful claims as well.

In addition, Mourinho has been critical of the Turkish referees in the league and VAR as well during the domestic campaign.

Mourinho's results in Turkey

In his first season with Fenerbahce, he finished second in the league standings with 84 points, 11 points short of the top where Galatasaray took the league title.

In the Europa League, the club went down in the Round of 16 clash against Rangers, where they fell short during the penalty shoot-out, despite coming back with a 2-0 win in the second leg to even things out.Now his future remains uncertain with the club and it will be interesting to see of 'The Special One' will continue in Turkey or if he will make the move to another club or better yet, a Premier League return with another club.

Indian football body drops ISL from 2025-26 calendar, future of league in doubt

- AIFF's official 2025–26 calendar omits Indian Super League
- ISL organisers inform clubs season won't start without MRA clarity
- FSDL manages ISL under a Master Rights Agreement expiring December 2025

New Delhi. The All India Football Federation has dropped its top-tier tournament – the Indian Super League – from its roster for 2025–26. The AIFF, in an official release, put out its calendar for 2025–26, which did not feature the competition, which has been running since 2014.According to media reports, uncertainty looms over the future of the Indian Super League. Several clubs have



been informed by the league's organisers that the next season will not begin until there is clarity on the Master Rights Agreement (MRA), According to the Times of India. A MRA is a legal contract that outlines the ownership and usage rights of a product in use, in this case, the ISL.Football Sports Development Limited (FSDL) — a joint venture between Reliance and Star — manages the ISL and serves as the

commercial partner of the All India Football Federation (AIFF). According to TOI, the FSDL signed a 15-year MRA with AIFF in 2010, under which it pays the federation either Rs 50 crore annually or 20% of total revenue, whichever is higher. This agreement is set to expire in December 2025.Since last week, senior FSDL officials have met club owners individually and informed them that the ISL won't start unless the MRA's future is clarified,” a source told TOI.

“It's well known that the MRA can't be finalised overnight. And with the Supreme Court expected to rule on the new AIFF Constitution soon, there's widespread uncertainty,” the source added.

Gautam Gambhir will enjoy working with a young captain: Sanjay Manjrekar

- Manjrekar believes Gambhir will relish working with a young captain like Gill
- He compared Gill's appointment to Azharuddin who was made captain in the 90s
- Manjrekar feels Gill will not come into the series under pressure

New Delhi. Former Indian cricketer Sanjay Manjrekar believes that the head coach of the Indian cricket team, Gautam Gambhir, will enjoy working with a young captain as they prepare to embark on their first big challenge, the England tour, to begin their new World Test Championship (2025-2027)



season.Manjrekar compared the results seen in India's T20I side, where Suryakumar Yadav was made the new captain after Rohit Sharma's retirement from the shortest format, following the T20 World Cup win. He believes that Gambhir will be able to bring out similar results in red-ball cricket with Gill at the helm.Gill was appointed captain of the Test side before the tour of England. He replaced Rohit Sharma, who retired from the longest format of the game weeks before Virat Kohli called it quits. Rishabh Pant was named vice-captain of a side that is undergoing

transition."Gautam Gambhir, as coach, will enjoy a young captain with him. You can see him as a coach when he's playing with Suryakumar Yadav as the Indian captain versus, you know, Rohit Sharma. He'll enjoy that job. So there's going to be a better kind of relationship between the captain and the coach," Manjrekar told ESPNcricinfo.

'GILL HAS NOTHING TO LOSE'

Manjrekar compared Gill's appointment to be similar to that of Mohammed Azharuddin, who was made captain back in 1989 following Krishnamachari Srikkanth's removal."The advantage that Shubman Gill has, this team has it was a bit like the team in the 90s when we went to New Zealand, where Mohammed Azharuddin, out of the blue as a young cricketer, was made the captain. You go with the feeling that you've got nothing to lose," he commented.The former cricketer is also of the opinion that Gill may have had to push himself for the role, considering the senior stalwarts like Virat Kohli and Rohit called time on their Test careers.

If Shubman Gill shows white-ball form at No.4, the world is his oyster: Dinesh Karthik

New Delhi. Former India wicketkeeper-batter Dinesh Karthik said Shubman Gill will be well served if he is able to replicate his white-ball form in Test cricket. Gill will take up a new role in the batting order as he will be India's new No.4 following the retirement of Virat Kohli in Test cricket. The India captain's new role was revealed by Rishabh Pant during the press conference on Wednesday, June 18.

This will be the third new batting spot for Gill since the start of his Test career, after beginning as an opener and playing at No.3 in the past few years. Speaking in a video on his official Instagram account, Karthik said that Gill would know about the expectations on him and the new India captain will be eager to win over the dressing room."Shubman Gill, who is going to take over the mantle from the King. That's a big one, but he knows. He wants to win that dressing room. If he gets going with the bat and shows the form he has shown in white-ball cricket, the world is his oyster," said Karthik.The pressure is certainly on India's new Test skipper. Considering the lack of runs from the batters in the last few series, Gill will certainly be expected to shoulder that responsibility while also ensuring his captaincy when on the field is on the mark.Gill has scored 1893 runs in 32 Tests, scoring six hundreds.



The Punjab Kings captain, however, has struggled in overseas conditions, especially in SENA (South Africa, England, New Zealand and Australia), averaging. Gill averages 25.70 in 11 Tests. Gill has scored only two fifties, both of them coming in Australia. The young captain has managed just 88 runs in three Tests at an average of 14.66.In contrast, Gill has 2775 runs in one-day internationals at an average of 59.04. He has hit eight hundreds, including a double hundred in his nascent career.Vice-captain Rishabh Pant confirmed Gill will bat at No. 4, a position that was long occupied by Virat Kohli who retired in May.

Karthik named his playing XI for the first Test and started off with KL Rahul and Yashasvi Jaiswal at the top of the order. The former wicketkeeper-batter felt that Jaiswal was ready for the challenge and said that Sai Sudharsan, who impressed in IPL 2025, will be at No.3.

Hope both of us play together for long: KL Rahul lauds childhood buddy Karun Nair's resolve

Rahul, who had a stellar IPL season with the bat, backed Nair to do well in his comeback series.

LEEDS. Senior batter K L Rahul is quite excited about Karun Nair's return to India's Test fold in the five-match series against England starting here on Friday as he believes that his childhood teammate has displayed commendable resolve while dealing with the hardships of being left out in the past.Nair and Rahul, both 33, have played age-group cricket together since their childhood and are close friends.

While Rahul has been a part of the Indian set-up, Nair endured a prolonged eight-year snub despite a good Test beginning, including a triple hundred against England.

"We started playing cricket as 11-year-old boys together and we have been on this journey ever since. Both of us have had our ups and downs. He got his opportunity, scored a triple hundred, faced a bit of tough time after that for a lot of reasons," Rahul told IPL side Delhi Capitals' media team after the season that concluded earlier this month."But what has stood out is the way he has performed in the last 2-3 years," he added referring to Nair's stellar run for Karnataka in the domestic circuit. Rahul said Nair relied on going "back to basics" during his time away from international cricket."We have spoken about his time in the UK and him having played County cricket, and the difficulties and the challenges that he faced.

"To have that drive to make a comeback to the Indian team despite all the hardships is commendable. I hope both of us can play for a very long time for the Indian team," he



said.Rahul, who had a stellar IPL season with the bat, backed Nair to do well in his comeback series.Talking about his own preparations for the series, the right-handed batter said he began right after the IPL."I spoke to my coach as well to get prepared for this assignment. It's always a challenge coming to England as they are a pretty good side, especially when they play at home. It's

going to be a challenge for all of us as we are a comparatively young team," he said.

Kohli, Rohit will be missed

Rahul reiterated that the dressing room would miss Virat Kohli and Rohit Sharma, both of whom retired from Tests last month."Virat and Rohit have been the pillars of Indian cricket for the last decade or so, and not having them around will be a huge miss. In my whole career so far, I have never walked into a team where there is no Virat or Rohit," he said."The 50-odd Test matches that I have played, either Virat or Rohit or both of them have been there. To walk into that dressing room feels a bit strange. But of course, you have to respect their decision."They have given absolutely everything for the country and they will remain legends of Indian cricket. But it's time for the rest of us to step up," he concluded.



Parineeti Chopra

Hints At Why She Skipped Mannara Chopra's Father's Funeral

Parineeti Chopra has seemingly broken her silence on why she skipped her cousin Mannara Chopra's father's funeral in Delhi. The actress took to Instagram to share a picture of a serene lake geo-tagged to London, UK, in the wee hours of June 19. Mannara's father's funeral was held in Delhi on June 18.

Since Parineeti frequently visits Delhi due to Raghav Chadha's parliament sessions, many noted the actress's absence from her uncle's funeral. Parineeti Chopra's father, Pawan Chopra, and brother Sahaj Chopra were also present at the funeral and were seen consoling Mannara and her family. However, Parineeti herself was noticeably absent from the final rites. The actress later took to her Instagram Story to share picturesque locations from London, seemingly hinting at why she was missing from the last rites. While Priyanka Chopra Jonas, who lives abroad, could not attend either, she paid tribute on social media. Sharing a photo on Instagram Stories, Priyanka wrote, "You'll always be in our hearts. Rest easy, Raman uncle (fufaji). Om Shanti." Parineeti is yet to issue any statement or reaction about her uncle's death. Mannara Chopra bid a tearful farewell to her father, Raman Rai Handa, on June 16. The 72-year-old passed away in Mumbai, and the final rites were performed by his daughters, Mannara and Mitali Handa, who were visibly emotional throughout the ceremony. In one of the heartbreaking visuals from the funeral, Mannara was seen insisting on carrying her father's mortal remains herself. At one point, she nearly fainted and had to be supported by grieving family members, including her mother, Kamini Chopra Handa.

Mannara Chopra had earlier shared an official statement on her father's demise: "With profound grief and sorrow, we inform the sad demise of our loving father who left us for his heavenly abode on 16/06/2025. He was the pillar of strength for our family."

Raman Handa was a practising lawyer at the Delhi High Court. He is survived by his wife, Kamini and daughters Mannara and Mitali. Kamini is the paternal aunt of Priyanka Chopra and Parineeti Chopra, placing the family in close relation.

Mannara, known for her work in Telugu and Hindi films, garnered widespread attention after finishing as the second runner-up on Bigg Boss 17. She has continued to receive public support as she mourns the personal loss with her family.



Sonam Bajwa Looks Jaw-Dropped In Latest Photos, Disha Patani Calls Her 'Sexxy'



Sonam Bajwa is a fashion icon and there is no doubt about it. Each time the actress drops photos or videos of herself on social media, she leaves everyone completely stunned. On Wednesday too, the Punjabi heartthrob took to her Instagram handle and shared a series of pictures, which are now setting fire online. In these latest clicks, Sonam Bajwa was seen posing in a grey tank top with a body hugging skirt. She was also seen holding a matching jacket in her arms, which covered one of her shoulders. The actress ditched accessories, opted for minimal makeup and left her tresses open. Needless to say, she looked breathtakingly gorgeous as ever.

Soon after the photos were shared online, several fans and followers reacted to it and praised Sonam. While Tamannaah Bhatia dropped fire emojis in the comments box, Disha Patani called the actress "sexxy". Jacqueline Fernandez also dropped a red heart and a fire emoticon in the comments section.

On the work front, Sonam Bajwa was recently seen in Housefull 5. The film is produced by Sajid Nadiadwala's Nadiadwala Grandson Entertainment and has one of Bollywood's largest ensemble casts in recent years. Akshay Kumar, Riteish Deshmukh and Abhishek Bachchan play the lead roles, with Fardeen Khan, Nana Patekar, Jackie Shroff, Ranjeet and Johnny Lever serving as supporting characters. The female cast includes Jacqueline Fernandez, Nargis Fakhri and Soundarya Sharma, with Chunky Panday and Dino Morea also playing prominent roles.

Housefull 5 starts on a luxurious cruise liner and centres on a murder mystery. Shortly after a billionaire proclaims that his fortune will be left to his successor, Jolly, he is found dead. But here's the catch: there are three Jollys on board, and each of their girlfriends is a prime suspect in the crime. Housefull 5 received mixed reviews from all and has earned around Rs 160 crore at the Indian box office as of now. Moreover, the global box office collection for Housefull 5 stands at Rs 243 crore.

There Is A Reason Why Jackie Shroff Is The 'OG Bhidu' Of Bollywood



Jackie Shroff's charm and swag are unmatched. Known for using the catchphrase 'Bhidu,' many find his style and personality to be effortlessly unique, which resonates with fans even today. On Tuesday night, the veteran star made a stylish appearance as he stepped out in the city for a meeting, seemingly for a new project. In a video shared on Instagram, the Singham Again actor was seen stepping out of a building after wrapping his meeting. On his way to his car, the actor took a moment and posed for the shutterbugs stationed outside the building. During this, the senior actor also engaged in a fun chat with the paparazzi.

Jackie Shroff's charm and swag are unmatched. Known for using the catchphrase 'Bhidu,' many find his style and personality to be effortlessly unique, which resonates with fans even today. On Tuesday night, the veteran star made a stylish appearance as he stepped out in the city for a meeting, seemingly for a new project.

In a video shared on Instagram, the Singham Again actor was seen stepping out of a building after wrapping his meeting. On his way to his car, the actor took a moment and posed for the shutterbugs stationed outside the building. During this, the senior actor also engaged in a fun chat with the paparazzi.

On the work front, Jackie is riding high on the success of his recently released 'killer-comedy' Housefull 5. Released on June 6, the film is directed by Tarun Mansukhani and produced by Sajid Nadiadwala.

It also featured an ensemble cast including: Akshay Kumar, Fardeen Khan, Abhishek Bachchan, Riteish Deshmukh, Sonam Bajwa, Jacqueline Fernandez, Nargis Fakhri, Chunky Panday, Johnny Lever, Chitrangada Singh, Sanjay Dutt and others.

In the film, Jackie portrayed the role of a cop, Chief Inspector Baba and his fun banter with colleague Sanjay Dutt, Bhidu, was one of the key highlights of the film. Up next, the veteran actor will be seen in Anupam Kher's second directorial project, Tanvi The Great. The star will be playing the role of Brigadier Joshi in the film. Last month, Anupam took to Instagram to share Jackie's look from the film, in which he was seen clad in an Army uniform. The film is slated to hit the big screens on July 18 and will face a clash with Yash Raj Films' upcoming romantic drama, Saiyaara featuring debutant Ahaan Panday and Aneet Padda.

Kriti Sanon

Joins Dhanush For Raanjhanaa Screening; Sonam Kapoor Gives It A Miss

As Aanand L Rai's Raanjhanaa approaches its 12th anniversary on June 21, 2025, the film continues to resonate deeply with audiences. A special fan screening of the 2013 romantic classic was held in Mumbai ahead of the milestone, and it turned into a nostalgic evening for movie lovers. Dhanush, who played the iconic Kundan Shankar, arrived at the event along with director Aanand L Rai and



actor Kriti Sanon, who will be seen next with Dhanush in Rai's upcoming project Tere Ishk Mein. Notably, Sonam Kapoor, the original film's lead actress, was missing from the celebration.

On the red carpet, Kriti Sanon looked striking in a scalloped wine-hued cut-out bodice paired with a flowy coral-orange

skirt. Her open hair, soft makeup, and confident aura completed the look—elegant and playful, much like her onscreen presence. Dhanush, on the other hand, opted for an effortlessly sharp black suit with a matching tee and layered necklaces. His sleeves were rolled up, adding a hint of casual charm to his tailored look.

Speaking about Raanjhanaa, Dhanush had once shared, "Aanand Rai did not choose me for Kolaveri Di, but for my National Award-winning film Aadukalam. Frankly speaking, I did not have to go through any rigid preparation for the role."

Reflecting on his Hindi dialogues, the actor recalled the challenge of dubbing all his lines, "It was tough but the writer Hemanshu and editor Hemal guided me all through the pauses and punches." He also credited Sonam Kapoor for supporting him during filming, adding, "She helped me understand so many things... it must have been difficult for her to act with me." Director Aanand L Rai has always believed Dhanush was the perfect choice. "I needed someone who could look vulnerable on screen. When I saw Aadukalam, I liked him immediately—he looked honest and ordinary, which was the demand of the character," he had told India Today.

Raanjhanaa was re-released in theatres on February 28, 2025, rekindling love for its music and storytelling. Rai noted, "It's fantastic that people still listen to Raanjhanaa's music and shower the same kind of love. It's a film very close to my heart."

